



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 1984/फाल्गुन 11, 1905

No. 33]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 1984/PHALGUNA 11, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

बजट 1984-85

(भाग क)

वित्तमंत्री का बिनांक 29 फरवरी, 1984 का भाषण

सं० एक० 15(1)-बी०(बी)/84 :—में वर्ष 1984-85 का बजट
प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ।

2. यह बजट राष्ट्रीय आय और कृषि के क्षेत्र में हुए प्रबल सुधार
और हमारे भुगतान-शेष में हुई उतनी ही प्रभावशाली वृद्धि की पुष्टि
में तैयार किया गया है। दो दिन पहले सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई
“आर्थिक समीक्षा” में इन तथ्यों और अर्थव्यवस्था की अन्य बातों के बारे
में विस्तार से चर्चा की गई है। अतः मैं यहां वर्तमान आर्थिक स्थिति की
समीक्षा संक्षेप में ही करूंगा।

3. जैसा कि सदन को मालूम है, देश को 1979-80 से 1982-83
की अवधि में दो वर्ष तक गम्भीर सूखे और एक वर्ष तक कमजोर मानसून
की स्थिति से गुजरना पड़ा। खाद्यान्न का उत्पादन जो 1978-79 में
1,320 लाख मेट्रिक टन के स्तर तक पहुँच गया था, परवर्ती वर्ष में
घट कर 1,100 लाख मेट्रिक टन रह गया। 1981-82 में यह कुछ
बढ़कर 1,330 लाख मेट्रिक टन हो गया, लेकिन भीषण सूखा पड़ने की

वजह से फिर 1982-83 में घटकर 1,280 लाख मेट्रिक टन हो गया।
चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन में काफी अधिक प्रगति हुई है और
संभावना है कि हम पिछली कमी को पूरा ही नहीं कर लेंगे बल्कि पिछले पिछले
स्तर से भी काफी ऊपर निकल जाएंगे। आभास है कि 1983-84 में खाद्यान्न का
उत्पादन 1,420 लाख मेट्रिक टन के स्तर से भी आगे बढ़ जाएगा। कृषि के
उत्पादन में कुल मिलाकर पूर्ववर्ती वर्ष की अपेक्षा सम्भवतः 9 प्रतिशत की
वृद्धि होगी। सम्मानित सदस्य सहमत होंगे कि यह हमारी कृषि संबंधी कार्य-
नीति के ठीक होने और हमारे किसान भाइयों की कड़ी मेहनत का प्रबल
प्रमाण है।

4. औद्योगिक क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में गत वर्ष की अपेक्षा सुधार हुआ है,
लेकिन औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की गति अब भी धीमी प्रतीत होती है।
चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक वृद्धि की दर सम्भवतः 4.5 प्रतिशत के आस-पास
रहेगी। जबकि 1982-83 में यह दर 3.9 प्रतिशत थी। 1979-80 के बाव
की चार वर्ष की अवधि में औद्योगिक वृद्धि की औसत दर 5 प्रतिशत से थोड़ी
सी अधिक बैठेगी। यह औद्योगिक क्षेत्र की क्षमता से काफी नीचे है। यदि
हमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर को ऊँचा रखना है और
आगामी वर्षों में अपने बढ़ते हुए अधिक वर्ग को रोजगार मुहैया कराना है
तो हमें औद्योगिक क्षेत्र में 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि की दर का लक्ष्य
रखना होगा।

5. वर्ष 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय आय में 6 से 7 प्रतिशत के बीच वृद्धि
होने की संभावना है। वर्तमान सरकार के शासन-भार सम्भालने के बाव के इस

चार वर्षों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की औसत दर लगभग 5.4 प्रतिशत रही है जो किसी भी पिछली आयोजना के पहले चार वर्षों में प्राप्त की गई वृद्धि की दर जंजी है। इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की औसत दर से वृद्धि हुई होगी। यह उपलब्धि अत्यन्त प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण और भीषण सूखे की पृष्ठभूमि में देखने पर और भी उल्लेखनीय प्रतीत होगी।

6. वर्ष 1981-82 और 1982-83 की प्रमुख विशेषता यह थी कि इन वर्षों में मुद्रास्फीति की दर बहुत ही कम रही। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जो 1979-80 में 21.4 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, उसे 1980-81 में 16.7 प्रतिशत पर और उसके बाद 1981-82 के अंत में केवल 2.4 प्रतिशत के निम्न स्तर पर ला दिया गया। 1982-83 के अंत में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 6.2 प्रतिशत थी जो एक सूखे के वर्ष के लिए अनामान्य रूप से नीची है। लेकिन चार वर्ष के दौरान बहुत बढ़िया फसल होने के बावजूब, मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में तेजी से वृद्धि हुई है। मानसून के आने में शुरु में देरी हो जाने और अर्थव्यवस्था में नकदी-बाहुल्य होने से वर्ष के पहले भाग में कीमतों पर दबाव पड़ा। फसल की कटाई के बाद, अच्छी फसल के अनुकूल प्रभावों के कारण प्रताड़ (दालों से भिन्न) की कीमतों में गिरावट आई। किन्तु, आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से कुछ वस्तुओं, जैसे दालों, कृतिपय खाद्य तेलों, रबर, चाय और कपास की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो जाने की वजह से इस गिरावट का असर काफी हद तक कम हो गया। इसके परिणामस्वरूप, कीमतों में आम तौर पर सितम्बर के अंतिम दिनों में जो मौसमी गिरावट आया करती है वह कमजोर रही।

7. जैसा कि सदन को मालूम है, सरकार ने सूखे के असर को कम से कम करने और कीमतों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। गेहूं, चनी, और खाद्य तेलों जैसी संवेदनशील वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए अधिक मात्रा में खरीदने, उपलब्ध कराने और जारी करने के लिए कार्यवाई की गई। बैंकिंग प्रणाली में विद्यमान नकदी-बाहुल्य को समेटने और सरकार के व्यय को कम करने के लिए भी कदम उठाए गए। आन्तरिक उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से कपास और सी०टी०सी० चाय के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। आवश्यकतानुसार और भी उपाय किए जाएंगे ताकि इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था हो सके कि 1979-80 जैसा अनुभव फिर न हो जबकि कीमतों में 21 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हो गई थी।

8. अब मैं यह बताऊंगा कि देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी भुगतान की स्थिति कैसी रही है। पिछले वर्ष के अपने बजट भाषण में मैंने सदन को 1982-83 में हमारे भुगतान-शेष में हुए सुधार की जानकारी दी थी। मुझे यह कहने हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि 1983-84 में इस स्थिति में और भी आगे सुधार हुआ है। व्यापारिक घाटा, जो 1981-82 में 5,800 करोड़ रुपए का था, घट कर 1982-83 में लगभग 5,500 करोड़ रुपए का रह गया और चार वर्षों में उसके और घट जाने की आशा है। अदृश्य मदों के खाते की प्राप्ति में भी वृद्धि होती रही है और अनिश्चितियों को रकम जमा कराने के लिए जो प्रोत्साहन दिए गए वे बहुत ही सफल रहे हैं। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से की गई निकामियों को हिसाब में शामिल करते हुए, चार ब्रितीय वर्ष में 10 फरवरी तक 662 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

9. वर्ष 1979-80 में हमारे भुगतान-शेष की स्थिति में तेजी से गिरावट आने के बाद, हमने उसे नियंत्रण में रखने के लिए जो कार्य-नीति अपनाई थी उससे बहुत फायदा हुआ है। हमारे भुगतानों की स्थिति में सुधार को देखते हुए, सरकार ने स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तारित कोष सुविधा के अंतर्गत 1.1 अरब एस डी ड्रार की शेष राशि को न लेने का निश्चय किया है। विसम्बर, 1981 में इन सदन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण पर चर्चा रही बहुत से भाग लेते हुए प्रधान मंत्री ने कहा था :

यह हमें उधार लेने के लिए मजबूर नहीं करता और न ही हम उधार लेते जब तक कि उधार लेना राष्ट्र के हित में नहीं होगा। हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम स्वीकार किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता जो कि हमारी पोषित और संसद् द्वारा स्वीकृत नीति के अनुकूल न हो। यह तो कल्पना-योग है कि कोई यह भोचे कि हम किसी ऐसी बाहरी एजेंसी से सहायता

स्वीकार कर लेंगे जो हमसे ऐसी शर्तें मनवाए जो हमारी इन नीतियों के साथ मेल न खाती हों।

यह बात उस समय भी सच थी और आज भी सच है।

10. अपने आपको कसाई समझने वाले कई लोगों ने जो सर्वसाधारण की भविष्यवाणी की थी उसे झूठा साबित करते हुए हमारी अर्थव्यवस्था हमारे समाज के प्रयत्नों के फलस्वरूप और अधिक मजबूत हो गई है। हमें जिन भयंकर दुष्परिणामों की चेतावनी दी गई थी उनमें से कोई भी दुष्परिणाम घटित नहीं हुआ। हमने आर्थिक सहायता (समिडी) में कोई कटौती नहीं की है। हमने किसी का बेटन कम नहीं किया है। हमने आयोजना के मामले में भी कोई समझौता नहीं किया है। हम ऋण संकट में भी नहीं फंसे हैं। हम गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों अथवा अपनी जनता की भलाई से संबंधित अपने बचनों से भी विमुख नहीं हुए हैं। हम भलीभांति सोच-समझ कर इस ऋण व्यवस्था में शामिल हुए थे और अब हम शान के साथ इस व्यवस्था से बाहर आ गए हैं।

11. हम आशा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ऋण व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध शेष राशि को न लेने के हमारे निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, कुछ हद तक, अन्य विकासशील देशों की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में सहायता देने में मदद मिलेगी। यह सराहनीय है कि विस्तारित कोष सुविधा प्रबंध की सम्पूर्ण अवधि में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ हमारे संबंध सद्भव और सौहार्दपूर्ण रहे हैं।

12. तथापि, आत्मसंतुष्ट हो कर बैठ जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें उन नीतियों को आगे भी जारी रखना होगा जिनके ये अनुकूल परिणाम निकले हैं। अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयातों में बचत करने के लिए और निर्यातों में वृद्धि करने के लिए और भी कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। तेल को छोड़ कर हमारे बाकी निर्यातों में, 1983-84 के पहले सात महीनों के दौरान 9.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है। पिछले कुछ समय से विश्व व्यापार में चल रहे गतिरोध को देखते हुए, यह एक काफी अच्छी प्रगति कही जा सकती है। वृद्धिशील अर्थ-व्यवस्था की आयात संबंधी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और ऋण परिशोधन अनुपात को प्रबंधयोग्य स्तर पर रखने के लिए हमें हमसे भी बढ़िया काम करने की जरूरत होगी।

13. सरकार ने सरकारी क्षेत्र में निवेश के लिए साधन जुटाने के हेतु और आयोजना का वित्तपोषण करने के उद्देश्य से सार्वजनिक बचतों की दर में वृद्धि करने के लिए पिछले चार वर्षों में कई कदम उठाए हैं। कर की दरों के समायोजन के अलावा, विनीय परिसम्पत्तियों के रूप में बचतों के लिए अधिक प्रोत्साहन देने के लिए भी राजकोषीय साधन का इस्तेमाल किया गया है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए जमा-राशियों पर व्याज की दरों में वृद्धिकारी संशोधन किए गए। ये नीतियां बहुत ही सफल सिद्ध हुई हैं, और अल्प बचतों तथा साविधिक जमा के रूप में धनराशियों की प्राप्ति आशा से अधिक हुई है। आने वाले वर्षों में राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण काम यह होगा कि वह इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा दे।

14. साधन जुटाने की अपनी कार्य-नीति पर विचार करते हुए हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे करों की दरें अपेक्षाकृत ऊंची हैं, लेकिन कर का आधार छोटा है। काले धन और कर-अपवंचन की बुराईयों से भी निपटना होगा। सरकार कर-अपवंचकों के साथ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही, हमें यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जहां तक सम्भव हो, कर प्रणाली अपने आप में कर-अपवंचन को प्रोत्साहन देने वाला साधन न बन जाए। इसलिए कर प्रणाली को सरल करने और युक्तिसंगत बनाने के कार्य हमारी राजकोषीय नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्य बने रहने चाहिए।

15. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को 1982-83 में 618 करोड़ रुपए का निवल लाभ हुआ था। हालांकि सरकारी क्षेत्र के बहुत-से उद्यमों ने 1983-84 में भी लाभ दिखाया जारी रखा फिर भी उनका कार्य-निष्पादन कुल मिलाकर आशाओं के अनुरूप नहीं रहा है। लाभकारिता में कमी आने का प्रमुख कारण यह था कि इस्पात और कोयला जैसे कुछ क्षेत्रों में हाजि हुई थी। सरकार ने उनके कार्यचालन में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना

होगा कि पूँजी का उपयोग अधिक कुशलतापूर्वक किया जाए ताकि भविष्य में विस्तार के लिए अधिक साधन उपलब्ध हों।

16. अपनी सामाजिक वचनबद्धताओं को पूरा करने और रोजगार की बचाने के लिए सरकार को बहुत-से ऋण एककों को हाथ में लेना पड़ा और नए साधन जुटाने के लिए नए ऋण रखना पड़ा। हालांकि उनमें से कुछ की हालत ठीक हो गई है, मगर बहुत-से एकक अब भी घाटे में चल रहे हैं। अब समय आ गया है जब कि सरकारी क्षेत्र के ऋण एककों के कार्य-विप्लवन की भली भाँति समीक्षा की जाए ताकि हमारे साधनों पर कम बोझ पड़े। सरकार का ऐसा करने का प्रस्ताव है। प्राथमिक महत्वता ही किसी उद्योग को जीवित रखने की प्रमुख कसौटी होनी चाहिए।

17. चालू वर्ष के दौरान बैंकों के पास जमा-राशियों में जो वृद्धि हुई है वह ऋण विस्तार के लिए उनकी धनराशियों की जरूरतों की अपेक्षा काफी ज्यादा है। अत्याधिक, इसके कारण बैंकिंग प्रणाली में कुछ नकदी-बाहुल्य उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में, और सरकारी निवेश के लिए कुछ साधनों को जुटाने के उद्देश्य से, यह बांछनीय समझा जाता है कि एक और वित्तीय योजना लागू की जाए जिसकी विशेषताएँ मोटे तौर पर वही हों जो बैंकों की लम्बी अवधि की जमा योजनाओं की होती हैं। इस योजना के अंतर्गत, जिसे "राष्ट्रीय जमा योजना" कहा जाएगा, कुछ अभिहित केन्द्रों से चार साल की परिपक्वता वाली जमा-राशियों के प्रमाणपत्र खरीदे जा सकेंगे। निवेशकर्ता को इन प्रमाणपत्रों को एक साल बाद भुनाने का विकल्प होगा। यदि ये राशियाँ चार वर्षों तक जमा रखी जाएंगी तो ब्याज की दर 10.5 प्रतिशत होगी और यदि ये राशियाँ तीन, दो और एक वर्ष के लिए जमा रहेंगी तो इन पर क्रमशः 10-9 और 7 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। इन जमा-राशियों के ब्याज पर आय-कर अधिनियम की धारा 80D के अंतर्गत 10,000 रुपये की पूर्ण सीमा तक कर से छूट प्राप्त होगी। इस योजना के अंतर्गत एक निश्चित समयावधि में 500 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने का लक्ष्य रखा गया है। मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि यह एक अल्पकालीन योजना है और इस लक्ष्य के प्राप्त हो जाने के बाद इसे समाप्त कर दिया जाएगा अथवा यदि मौद्रिक घटनाक्रम को देखते हुए आवश्यक हुआ तो इसे पहले समाप्त किया जा सकता है।

18. पिछले साल सरकार द्वारा नियुक्त की गई वित्तीय संस्थाओं संबंधी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, "संपरिवर्तनीयता खंड" में कतिपय परिवर्तन करने का निश्चय किया गया है। संपरियोजनाओं की पूँजीगत लागत और अलावसंसीकृत क्षेत्र में निवेश की सीमा में हुई वृद्धियों को दृष्टिगत रखते हुए, संपरिवर्तनीयता खंड से छूट के प्रारम्भिक सौपना को 1 करोड़ रुपये के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

19. इसके अलावा, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत न आने वाली कंपनियों के मामले में संपरिवर्तनीयता खंड लागू नहीं किया जाएगा, यदि ऐसी कंपनी में सभी वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी धारिता 26 प्रतिशत से अधिक होगी। किन्तु एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियों के व्यापारिक धरानों के मामले में, 40 प्रतिशत की मौजूबा सीमा लागू रहेगी। "उद्योग-रहित" जिलों में निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, इन जिलों में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित एककों के संबंध में संपरिवर्तनीयता खंड से पूरी तरह छूट मिलेगी। सहायता-प्राप्त कंपनियों के बोर्डों में नियुक्त किए गए संस्थाओं के नामजब निदेशकों के कार्यभार में भी सुधार किया जा रहा है। इस विषय में और अन्य संबंधित पहलुओं पर विस्तृत मार्गनिर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

20. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उद्योगों के प्राधुनिकीकरण के लिए उदारतापूर्वक वित्तीय सुविधाएँ देता रहा है। इस प्रयोजन के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो योजना है वह हाल में सभी औद्योगिक एककों पर लागू कर दी गई है और इस योजना के अंतर्गत 4 करोड़ रुपये तक की राशि ब्याज की 12.5 प्रतिशत की दर पर दी जा रही है। प्राधुनिकीकरण की योजनाओं की वित्तीय लागत को कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि 4 करोड़ रुपये तक के ऋणों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की योजनाओं के अंतर्गत ब्याज की दर, अगली सूचना तक, घटा कर 11.5 प्रति

शत की जाएगी। कमजोर एककों को इस राशि तक की सहायता हमसे भी नीची, यानी 10 प्रतिशत की दर पर दी जाएगी।

21. सदन को मान्य है कि सरकार वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने की बांछनीयता पर विचार करती रही है। जैसा कि मैंने अतः सदन को सूचित किया था, मैंने इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के विचार आमंत्रित किए थे। उनकी प्रतिक्रिया आम तौर पर अनुकूल थी। राज्य सरकारों से और व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के लिए और वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने की कार्यवाधियाँ निर्धारित करने के लिए, मैं एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नियंत्रक-महानिष्ठापरीक्षक के प्रतिनिधि और कुछ गैर-सरकारी सदस्य होंगे। इस समिति से अपनी रिपोर्ट सितंबर, 1984 के अंत तक प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

22. अब मैं 1983-84 के संशोधित अनुमानों और 1984-85 के बजट अनुमानों की ओर आता हूँ।

1983-84 के संशोधित अनुमान

23. सदन को याद होगा कि 1983-84 का केन्द्रीय क्षेत्र का आयोजना परिव्यय 13,870 करोड़ रुपये रखा था। इसे 8,390 करोड़ रुपये तक बजट से और 5,480 करोड़ रुपये तक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आन्तरिक तथा बजट-बाह्य साधनों से पूरा किया जाना था। सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों के आन्तरिक साधनों में कमी हो जाने के बावजूद, मेरा यही प्रयास रहा है कि वर्ष के दौरान कुल आयोजना परिव्यय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अब अनुमान है कि 1983-84 में केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 14,059 करोड़ रुपये होगा। बजटीय समर्थन से, बजट अनुमानों की अपेक्षा, 1,007 करोड़ रुपये की वृद्धि करके ऐसा करना संभव हुआ है।

24. डाक-तार आयोजना के लिए बजटीय समर्थन की राशि में 203 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। रेलवे के आयोजना परिव्यय में भी 54 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय समर्थन के साथ, 100 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। परिवहन और संचार क्षेत्र में, मैंने 'इसेट' जैसी अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए और दूरदर्शन के व्यापारिक क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त धनराशियों की व्यवस्था की है। विद्यायापन इसका संबंध की प्रगति को निरंतर बनाए रखने के लिए, बजट व्यवस्था में 250 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। रसायनों और उर्वरकों के लिए आवंटित राशि में 133 करोड़ रुपये की वृद्धि अधिकांशतः आन्तरिक साधनों में कमी हो जाने और वित्तपोषण की पद्धति में परिवर्तन होने के कारण की गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में, निर्माणधीन परियोजनाओं के कार्य की गति को तेज करने के लिए कोयला संबंधी परियोजनाओं की 30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि दी गई है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूँजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए 130 करोड़ रुपये की एक विशेष व्यवस्था की गई है। चालू वर्ष में प्रारम्भ किए गए नए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं। मैंने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के लिए भी व्यवस्था में वृद्धि की है।

25. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में 392 करोड़ रुपये की वृद्धि करके उसे 4,462 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,854 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें उन राज्यों को अग्रिम रूप से दी गई आयोजना सहायता की 190 करोड़ रुपये की राशि शामिल है जो विशेष रूप से चालू वर्ष की पहली छमाही में मानसून न आने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे। आसाम राज्य को 82 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आयोजना सहायता दी गई है, जिसका अधिकांश भाग उस राज्य में दंगों से पीड़ित लोगों को राहत देने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए दिया गया है।

26. आयोजना-भित्त व्यवस्था की सीमा रखने के लिए भरसक सावधानी बरती गई है। फिर भी, कुछ अपरिहार्य वचनबद्धताएँ थीं। राज्यों को दिए जाने वाले अर्धोपाय अधिमां के लिए और खपत-व्यापार करारों के अंतर्गत तकनीकी ऋणों के लिए 400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। कृषि संबंधी निविष्टियों (इनपुट) के लिए राज्यों को दिए जाने वाले अर्धोपाय अधिमां के

110 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों में 300 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है क्योंकि मूल्य बचतों की राशि अधिक मात्रा में एकत्र होने के कारण इन बचतों में उनका हिस्सा बढ़ जाएगा। चालू वर्ष की दूसरी छमाही में कोई 15 राज्यों में बाढ़ें और चक्रवातीय तूफान आए तथा भोलावृष्टि हुई। इन विपत्तियों के कारण पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 150 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रायोजना-भित्त अनुदान की व्यवस्था की गई है।

27. इसके अतिरिक्त, मैं राज्यों को 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रायोजना-भित्त सहायता देने के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। इस विषय में मैं बाद में राज्यों के प्रगले वर्ष के प्रायोजना परिषद पर विचार करते समय चर्चा करूँगा। 500 करोड़ रुपए के इस ऋण में से 400 करोड़ रुपए की राशि से राज्यों को अपने 1982-83 के घाटे साफ करने में सहायता मिलेगी।

28. रक्षा के लिए व्यवस्था को 5,971 करोड़ रुपए से बढ़ाकर संशोधित अनुमानों में 6,350 करोड़ रुपए कर दिया गया है। चालू वर्ष में, सरकारी कर्मचारियों के लिए भ्रजूर की गई अस्थिरता राहत और बोनस के कारण सरकार के सभी विभागों के संबंध में लगभग 280 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। प्रायतिष्ठ और स्वदेशी उर्वरकों पर दी जाने वाली प्राथमिक सहायता की राशि 250 करोड़ रुपए बढ़कर 1,048 करोड़ रुपए की हो जाएगी क्योंकि जून 1983 में उर्वरकों की उपभोक्ता कीमतों में कमी कर दी गई थी। चालू वर्ष के दौरान वित्तीय कठिनाइयों के कारण, सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों को, खासतौर से हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, राष्ट्रीय बस्स निगम और वित्तीय परिवहन निगम को, बजट में की गई व्यवस्था से अधिक प्रायोजना-भित्त सहायता की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कलकत्ता पत्तन और हाल्लिया चैनल के तलकथन (ड्रेजिंग) के लिए प्राथमिक सहायता की योजना को प्रगले वर्ष के अंत बढ़ाने का निश्चय किया गया है।

29. संशोधित अनुमानों में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपने बड़े हुए कोटे के संबंध में अधिदान देने के लिए, 502 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था भी शामिल की गई है। किन्तु, इसका बजट पर कोई निबल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि कोटे के अधिदानों के लिए की जाने वाली प्राययगियां तदनुसृत प्राप्ति से प्रसिस्तुलित हो जाती हैं। उपर्युक्त और अन्य परिवर्तनों को हिसाब में लेने पर, संशोधित अनुमानों में प्रायोजना-भित्त व्यय की राशि 24,773 करोड़ रुपए रखी गई है जबकि बजट अनुमानों में इसकी राशि 21,984 करोड़ रुपए की थी।

30. जहां तक प्राप्ति का संबंध है, प्राय-कर और सीमा-शुल्कों की प्राप्ति के बजट अनुमान संभवतः पूरे हो जाएंगे। निगम-कर की प्राप्ति में, बैंक कंपनियों द्वारा अधिक प्राययगियां किए जाने के कारण 203 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। संघ-उत्पाद-शुल्कों में भी, कच्चे तेल (क्रूड) और कोयले पर उपकरों की अधिक राशि प्राप्त होने के कारण 85 करोड़ रुपये की अधिक प्राप्ति होने का अनुमान है। केन्द्र का कर-राजसव, करों में राज्यों के हिस्सा भरा कर दिए जाने के बाद, 15,700 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि बजट अनुमान 15,460 करोड़ रुपए का था।

31. कर-भिन राजस्व के अंतर्गत, रेलवे के लाभांश के रूप में, बजट अनुमानों की अपेक्षा 127 करोड़ रुपए कम प्राप्त होने की संभावना है किन्तु यह कमी अन्य स्रोतों के अंतर्गत वृद्धि हो जाने से अधिप्रसिस्तुलित हो जाएगी, और चालू वर्ष में कर-भिन राजस्वों की कुल राशि, बजट अनुमानों की अपेक्षा 130 करोड़ रुपए अधिक होने की आशा है।

32. मुझे सबन को बताते हुए प्रसन्नता होती है कि पूंजी खाते की प्राप्ति के अंतर्गत, चालू वर्ष के दौरान मूल्य बचतों के निबल संग्रह की राशि 2,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है, जबकि बजट अनुमान 1,700 करोड़ रुपए का था। यह चालू वर्ष के बजट में मूल्य बचतों के लिए दिए गए प्रोत्साहनों का स्वागत-योग्य सुपरिणाम है। आशा है, तकनीकी ऋणों की बापसी प्राययगी से 1,150 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे जबकि बजट में 800 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था। व्यय को घटाने के बाद निबल प्राप्ति की राशि, बजट अनुमानों के 200 करोड़ रुपए के मुकाबले, 350 करोड़ रुपए होगी।

33. गैर-सरकारी भविष्य निधियों की विशेष जमाराशियों और ऐसी ही अन्य रकमों से बजट अनुमानों की अपेक्षा 190 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होने का अनुमान है। तेल क्षेत्र की अधिशेष धनराशियों की जमा रकमों, राज्य सरकारों को दिए गए अधोप्राय और अत्याधिक प्रथियों की अतिरिक्त वसूलियों और अन्य घट-बढ़ को हिसाब में लेने के बाद, चालू वर्ष में पूंजी खाते की प्रसिस्तियां 15,965 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि बजट अनुमानों में इनकी राशि 12,656 करोड़ रुपए दिखाई गई थी।

34. इस प्रकार कुल प्राप्ति की राशि 33,250 करोड़ रुपए से बढ़कर 36,929 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। इससे चालू वर्ष में बजटीय घाटा 1,695 करोड़ रुपए का रहेगा, जबकि बजट अनुमानों में 1,586 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था। इस राशि में 400 करोड़ रुपए की बहु विशेष ऋण सहायता की राशि शामिल नहीं है जो पूर्ववर्ती वर्ष 1982-83 के अंत के ओवरड्राफ्ट साफ करने के लिए राज्यों को दी गई थी। सदन अवश्य ही मुझ से सहमत होगा कि अपरिहार्य बजटीय तथ्यों के बावजूद, हम घाटे को विवेकपूर्ण सीमाओं में रख सकते हैं।

1984-85 के बजट का अनुमान

35. सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि जब हमारी सरकार ने जनवरी 1980 में शासन-भार संभाला था, उस समय हमारे सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य यह था कि प्रायोजना की प्रक्रिया को पुनरुज्जीवित किया जाए और विकास के कार्यक्रमों को नया बल प्रदान किया जाए। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि पिछले चार सालों में, हम सार्वजनिक निवेश की गति में अभूतपूर्व वृद्धि कर सके हैं।

36. वर्ष 1984-85 के लिए, केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का अनुमोदित प्रायोजना परिषद 30,132 करोड़ रुपए का होगा, जबकि 1983-84 में इसकी राशि 25,480 करोड़ रुपए की थी। 1984-85 के लिए केन्द्रीय प्रायोजना परिषद की राशि 17,351 करोड़ रुपए रखी गई है, जो कि 1983-84 के 13,870 करोड़ रुपए के अनुमोदित प्रायोजना परिषद से 25 प्रतिशत अधिक है।

37. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रायोजना परिषद की राशि 12,781 करोड़ रुपए रखी गई है, जबकि 1983-84 में अंतिम रूप से अनुमोदित परिषद की राशि 11,678 करोड़ रुपए की थी। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रायोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि 5,050 करोड़ रुपए की होगी, जबकि 1983-84 के बजट अनुमानों में यह राशि 4,462 करोड़ रुपए की थी और इस प्रकार इसमें चालू वर्ष में किए गए आर्बटन की तुलना में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

38. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के उपर्युक्त समूचे प्रायोजना परिषद के अंतर्गत अलग-अलग राज्यों की प्रायोजनाओं की स्थिति भिन्न-भिन्न है। कुछ राज्यों ने अपने वित्तों का प्रबन्ध बहुत अच्छी तरह किया है; वे अतिरिक्त साधन जुटाने में और उनका पर्याप्त प्रकार की प्रायोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रभावोत्पादक उपयोग करने में सफल हुए हैं और इस प्रकार उन्होंने अपने विकास और अपनी जनता की वृद्धि के लिए व्यवस्था की है। दुर्भाग्यवश, कुछ राज्यों ने अपने निजी कारणों से, अपने साधनों का इस्तेमाल बहुत-से अन्य प्रयोजनों के लिए किया है; उन्होंने अपने साधनों को, जिनमें जुटाए गए अतिरिक्त साधन शामिल हैं, विकास के लिए नहीं लगाया है और उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक से भी ओवरड्राफ्ट की बड़ी-बड़ी रकमें ले ली हैं।

39. ऐसे राज्यों को भी सहायता देने के लिए, समय समय पर विभिन्न सुविधाएं और अवसर दिए गए थे। छठी प्रायोजना के शुरू में ही 1,412 करोड़ रुपए की अधिम सहायता की बकाया राशि की वसूली स्थगित कर दी गई थी। यह इसलिए किया गया था ताकि राज्य साफ खाते के साथ मुहमात कर सकें। किन्तु राज्यों के ओवरड्राफ्ट फिर बढ़ गए और जून 1982 में मैंने 1743 करोड़ रुपए के मध्यमावधिक ऋण देकर राज्यों के पूर्ववर्ती वर्ष के इतिशेष घाटे को साफ करने का फैसला किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी राज्यों को उपलब्ध अधोप्राय की सीमाओं को दुगुना कर दिया। पिछले साल फिर, बजट प्रस्तुत करते समय मैंने केन्द्रीय सहायता के स्तर में वृद्धि करने की घोषणा की। ये सारे उपाय मुख्यतः राज्यों को इस बात की सहायता देने के लिए किए गए थे कि वे अपने वित्तीय

सामलों का पुनः समायोजन कर सकें और पर्याप्त आकार की अपनी आयोजनाओं को क्रियान्वित कर सकें।

40. दुर्भाग्य की बात है कि इन उपायों के बावजूद, कुछ राज्यों ने मार्च 1982 के बाद भी ओवरड्राफ्टों पर अत्यधिक निर्भर रहना जारी रखा। मार्च 1984 के अंत में उनके प्रस्तावित घाटों का उनकी आयोजनाओं के आकार पर कठोर प्रभाव पड़ेगा, यदि सामान्य परिपाटी के अनुसार, इन घाटों को उनकी अगले वर्ष की आयोजना में समायोजित किया जाएगा। इस समस्या को काबू में रखने के उपायों पर विचार करते समय मैं अपने आप को दुविधा में फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ। एक ओर, देश का कोई भी वित्त मंत्री किसी भी राज्य की आयोजना के आकार के विषय में उदासीन नहीं रह सकता। दूसरी ओर, यदि चूककर्ता राज्यों को सहायता दी जाती है तो सुप्रबंधित राज्यों की यह शिकायत उचित होगी कि उन्हें अपने बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए केन्द्र से न्यायोचित पुरस्कार नहीं मिला है।

41. पिछले कुछ सप्ताहों में, उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों से फिर विचार-विमर्श किया गया है, जिनके भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्ट की राशि बहुत अधिक थी। कुछ राज्य सरकारें इस बात के लिए सहमत हो गई हैं कि वे अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने और ओवरड्राफ्टों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगी। मैं स्वयं इस बात के लिए सहमत हो गया हूँ कि मैं भी राज्यों को प्रतिरिक्त सहायता देने के लिए और उपाय करूँगा ताकि जहाँ तक संभव हो राज्यों की आयोजनाओं को बचाया जा सके। ऐसा करते समय मैं गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गति को तेज रखने की आवश्यकता के प्रति विशेष रूप से सजग रहा हूँ। केन्द्रीय सहायता की राशि में भी और वृद्धि की जा रही है। इसे हिसाब में लेते हुए, आयोजना अवधि में कुल सहायता की राशि आयोजना प्रलेख में परिकल्पित 15,350 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले 17,790 करोड़ रुपये की होगी। इसके अलावा, जैसा कि मैंने पहले कहा है, मैंने 1983-84 के संशोधित अनुमानों में 500 करोड़ रुपये की प्रतिरिक्त व्यवस्था की है। इस विशेष सहायता से ये राज्य भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए अपने ओवरड्राफ्ट आंशिक रूप से साफ कर सकेंगे। राज्यों को यह भी बता दिया गया है कि उनके इतिरास घाटों को, भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमत अर्थापय सीमाओं तक, अगले वर्ष के आयोजना साधनों के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा।

42. उन राज्यों के मामले में जिन्होंने अपने वित्त का अच्छा प्रबंध किया मैं 1984-85 में उनको कुछ प्रतिरिक्त सहायता देने की एक उपयुक्त योजना बना रहा हूँ। यह न्यायसंगत और समुचित ही है।

43. अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि सबन मुझे इस बात के लिए सहमत होगा कि अपनी निजी साधन संबंधी कठिन समस्याओं के बावजूद, केन्द्रीय सरकार ने राज्यों की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो कुछ भी वह अधिक से अधिक कर सकती थी, किया है। बाकी जो कुछ करना है वह उन्हें स्वयं करना है।

44. छठी आयोजना की अवधि में, सरकारी क्षेत्र की आयोजना कुल मिलाकर, चालू कीमतों पर 110,000 करोड़ रुपये से अधिक की होगी। इसकी तुलना में पूर्ववर्ती पांच वर्षों का आयोजना परिस्य 46,700 करोड़ रुपये का था हालांकि इन पांच वर्षों में से तीन वर्ष ऐसे हैं जो पिछली सरकार के द्वारा संचालित "गैर-आयोजना" के हैं। वास्तविक रूप में भी, छठी आयोजना का परिस्य, पिछली किसी भी आयोजना के परिस्य की तुलना में, बहुत अधिक होगा। अध्यक्ष महोदय, यह वृद्धि चालू आयोजना की अवधि में विकास की गति को तेज करने में इस सरकार द्वारा प्राप्त सफलता का एक मापदण्ड है।

45. पिछले चार सालों में, वर्तमान सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के फायदे के लिए बहुत-सी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और 15 अगस्त, 1983 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित दो नए कार्यक्रम, अर्थात् ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगारों को निजी रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना शामिल है। इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम का उद्देश्य लक्ष्यगत विशिष्ट समूहों के लिए आमदनी और रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उत्पादक परिसंस्थितियों का निर्माण करना भी है।

46. अगले वर्ष की आयोजना तैयार करते समय, हमने इन कार्यक्रमों की और ऐसे अन्य कार्यक्रमों की भी जिनसे प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण निर्धनों को फायदा पहुंचता है, अधिक से अधिक समर्थन दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवंटित कुल राशि 932 करोड़ रुपये की होगी जो कि 1983-84 में रखी गई 480 करोड़ रुपये की राशि से लगभग दुगुनी है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 216 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की जा रही है; उसी ही राशि राज्यों द्वारा भी दी जाएगी। 1984-85 में इस कार्यक्रम के लाभानुभोगियों की संख्या अनुमानतः 30 लाख से अधिक होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए, 1984-85 के संबंध में 230 करोड़ रुपये के परिस्य की व्यवस्था की गई है; इस कार्यक्रम के लिए भी इतनी ही राशि की व्यवस्था राज्यों द्वारा की जाएगी।

47. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की परिकल्पना की गई है, के लिए आवंटित राशि को, 1983-84 के 100 करोड़ रुपये के मुकाबले, 1984-85 में बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से कुल मिलाकर, 1984-85 में ग्रामीण क्षेत्रों में 55 करोड़ कार्य-विषयों (मैन डेज) के रोजगार की व्यवस्था होगी। शिक्षित बेरोजगारों को निजी रोजगार के अवसर प्रदान करने के कार्यक्रम के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की जा रही है। जैसा कि सबन को मालूम है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई बजट व्यवस्था का उपयोग बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के एवज में पूंजीगत आर्थिक सहायता देने के लिए किया जाएगा। मैं यह बतला दूँ कि इन दो नए कार्यक्रमों के लिए, व्यय की प्रगति को देखते हुए, वर्ष के दौरान आवश्यकतानुसार और धनराशि की व्यवस्था की जाएगी।

48. वर्ष 1984-85 की आयोजना में, स्वतंत्र ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के लिए 243 करोड़ रुपये रखे गए हैं। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए 364 करोड़ रुपये की व्यवस्था स्वयं करेंगे। 1984-85 के दौरान 50,000 से अधिक समस्याग्रस्त गांवों को पीने के पानी की सुविधाएं मुहैया किए जाने की आशा है।

49. एकीकृत बाल विकास सेवाओं का कार्यक्रम हमारे उन प्रयत्नों का एक महत्वपूर्ण अंग है जिनसे हम अपने देश के पिछड़े इलाकों, गहरी गंदी नदियों और जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को मदद देना चाहते हैं। यह कार्यक्रम 820 खंडों में पहले से ही चल रहा है। 1984 के अंत तक, यह योजना सभी 1000 निर्धारित खंडों में पूरी तरह चालू हो जाएगी। इस योजना के लिए 36 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए, 1984-85 में कुल मिलाकर 78 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

50. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को फायदा पहुंचाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय आयोजनाओं में, 1983-84 के केवल 176 करोड़ रुपये की तुलना में, 1984-85 में 209 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। शिक्षा और संस्कृति के कार्यक्रमों के लिए आयोजना परिस्य को, जो 1983-84 में 155 करोड़ रुपये का था, काफी अधिक बढ़ाकर 1984-85 में 204 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए आयोजना परिस्य से लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि की गई है; इसके लिए 1983-84 में 460 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, अब 1984-85 में 605 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत 2 करोड़ लोग और आ जाएंगे।

51. सरकार की उपर्युक्त और अन्य सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताएं 20-सूत्री कार्यक्रम में परिलक्षित होती हैं, जिसे जोरदार तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय आयोजना में कुल 4,038 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो चालू वर्ष की व्यवस्था की अपेक्षा लगभग 47 प्रतिशत अधिक है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपबंधित किए जाने वाले परिस्यों को शामिल करते

हुए, 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए कुल व्यय 11,858 करोड़ रुपए की होगी, जो केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कुल वार्षिक आयोजना परिव्यय के लगभग 40 प्रतिशत के बराबर होगी।

52. कृषि के क्षेत्र में जो असाधारण प्रगति हुई है वह अर्थव्यवस्था के लिए सामर्थ्य का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस क्षेत्र के विकास को वर्तमान सरकार द्वारा दी गई उच्च प्राथमिकता अगले वर्ष की आयोजना में भी जारी रहेगी। इस प्रकार, कृषि मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कुल परिव्यय की राशि, चासू वित्तीय वर्ष के 556 करोड़ रुपए की तुलना में, 758 करोड़ रुपए की होगी। इस परिव्यय में राष्ट्रीय तेलहन विकास परियोजना के लिए 38 करोड़ रुपए की राशि शामिल है; इस परियोजना में और पहले से चले आ रहे अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत, 1984-85 में ही 9.4 लाख मेट्रिक टन के अतिरिक्त उत्पादन की परिकल्पना की गई है।

53. देश के आधारभूत ढांचे को और मजबूत करने के लिए विद्युत, कोयला, रेलवे और पत्तनों के लिए अधिक राशियों की व्यवस्था की जा रही है। विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 1,764 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो 1983-84 की तुलना में 44 प्रतिशत वृद्धि की व्योक्त है। कोयला विभाग की परियोजनाओं के लिए 1,310 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, जबकि 1983-84 में 1,076 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी; और 1984-85 में 1,520 लाख मेट्रिक टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 1984-85 में रेलवे के लिए 1,650 करोड़ रुपए की व्यवस्था है जो कि चासू वर्ष की अपेक्षा 23 प्रतिशत अधिक है। यह अंश की जाती है कि रेलों द्वारा बोना जाने वाला राजस्व उपार्जक मालावात 1984-85 में बढ़कर 2,450 लाख मेट्रिक टन हो जाएगा। पत्तनों के विकास के लिए 201 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें मंत्रालय बंदरगाह को गहरा करने के लिए 27 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

54. वेदोलिपय के लिए 3,127 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की जा रही है। इसमें अन्वेषण और उत्पादन के कार्यक्रमों के लिए 2,685 करोड़ रुपए और तेल शोधन तथा विपणन की विभिन्न योजनाओं के लिए 443 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। 1984-85 में लगभग 300 लाख मेट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। एक गैस पाइप-लाइन परियोजना के लिए भी 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। इस परियोजना के द्वारा बिजपुर, जगदीशपुर, आंबला, बबराला, शाहजहापुर और सवाई माधोपुर में स्थापित की जाने वाली नई उर्वरक परियोजनाओं को बेसीन गैस की सप्लाई की जाएगी।

55. इस्पात, अलौह धातुओं, कागज, सीमेंट और अन्य बहुत से क्षेत्रों के लिए, जो देश के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, पहले से अधिक धनराशियों की व्यवस्था की जा रही है। मैं सदन का ध्यान उन कार्यक्रमों की ओर भी बिलाना चाहता हूँ जो 1984-85 की आयोजना में विज्ञान और औद्योगिकी, प्राकृतिक साधनों के संरक्षण और पर्यावरण के सुधार के लिए शामिल किए गए हैं। पिछले अगस्त में इन्सेट-1 बी का भूकेंद्रिक कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करना हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशनों के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य का प्रमाण है। हमारे लिए यह एक गर्व की बात है कि भारत उन कुछ चुने हुए देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनमें दक्षिणी गुरु प्रदेश में स्थायी वैज्ञानिक केन्द्र स्थापित कर रहे हैं। भारत ही एक ऐसा विकासशील देश है जिसे समुद्री कायून सम्मेलन से "अग्रणी निदेशक" (पायनिअर इन्वेस्टर) के रूप में मान्यता प्राप्त होने की प्रतिष्ठा मिली है, जिससे हम गहरे समुद्री तलों के खनिज स्रोतों का उपयोग करने का अधिकार मिल गया है।

56. अंत में, मैं यह बताना चाहूंगा कि चुने हुए क्षेत्रों में बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहन देने की योजनाएं 1983-84 में शुरू की गई थीं, वे 1984-85 में भी जारी रहेंगी। जैसा कि सदन को मालूम है, ये योजनाएं बिजली बोर्डों के मंत्रालय में सुधार माने के लिए और छोटे

या सीमावर्ती किसानों के कार्यक्रमों, ग्रामीण जलपूर्ति योजना, शहरी गंदी बस्तियों में पर्यावरणिक सुधार, कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रों में सरणियों का निर्माण, और स्त्रियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा और बालिकाओं के लिए प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रमों को और बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। इस प्रयोजन के लिए 200 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि की व्यवस्था की जा रही है। कहीं ऐसा न हो कि सम्मानित सदस्य मुझे कोई ऐसा जादूगर समझ बैठें जो इतने कम साधनों से इतना अधिक कर सकता है। इसलिए मैं जल्दी से यह स्पष्ट कर दूँ कि ये प्रोत्साहन योजनाएं विनिर्दिष्ट योजनाओं के कार्य-निष्पादन के आधार पर अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था करने के लिए बनाई गई हैं। इनमें से प्रत्येक योजना के लिए अलग से भी यथेष्ट मात्रा में धनराशि की व्यवस्था की गई है।

57. मैंने 1984-85 की वार्षिक आयोजना के उद्देश्यों और उसकी मुख्य-मुख्य प्राथमिकताओं का बहुत ही संक्षेप में विवेचन किया है। इस संक्षेप में अतिरिक्त जानकारी बजट-पत्रों में उपलब्ध है।

58. आयोजना के लिए धार्यामय अधिक से अधिक परिव्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, मैंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि आयोजना-भिन्न व्यय निम्नतम स्तर पर रखा जाए। किन्तु कठिण वृद्धियां करना आवश्यक और अपरिहार्य है। मैं यह भी बताना चाहूँ कि राज्य सरकारों से होने वाली प्राप्ति और उनको की जाने वाली अदायगियों के अनुमान तैयार करने समय, आठवें वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों का ध्यान में रखा गया है। इस विषय में मैं सदन को पहले सूचित कर चुका हूँ। आयोग की अन्तिम रिपोर्ट अप्रैल, 1984 के अन्त तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

59. मैंने रखा व्यय के लिए, इस वर्ष के संशोधित अनुमानों के 6,350 करोड़ रुपए के मुकाबले, अगले वर्ष 6,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मुझे विश्वास है कि सदन इस बात में मुझसे सहमत होगा कि रखा के लिए सभी जरूरतों को देश की सुरक्षा के हित में पूर्णतः पूरा किया जाना चाहिए। अगले वर्ष ग्याज की अदायगियों की अनुमानित राशि, इस वर्ष के 4,850 करोड़ रुपए के मुकाबले, 5,600 करोड़ रुपए की होगी। उधार की राशि का अधिकांशतः हमारे विकास कार्यों का वित्तपोषण करने के लिए ली जाती है और ग्याज की अदायगियों की राशि में वृद्धि बचतें जुटाने की हमारी नीतियों की सफलता के कारण हुई है। खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता के लिए 850 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। स्वदेशी और आयातित उर्वरकों पर आर्थिक सहायता देने के लिए 1,080 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। निर्यात संवर्धन और विपणन विकास के लिए 530 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

60. केन्द्रीय सरकार को कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और पेंशन राहत आदि देने के लिए 1984-85 में 300 करोड़ रुपए की एकमुश्त व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं और समायोजन के स्वच्छ वाली अन्य व्यवस्थाओं को हिसाब में लेने पर, 1984-85 में कुल आयोजना-भिन्न परिव्यय अनुमानतः 26,066 करोड़ रुपए का होगा, जबकि 1983-84 के संशोधित अनुमानों में 24,773 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है।

61. जहाँ तक 1984-85 में प्राप्तियों का संबंध है, कराधान के वर्तमान स्तरों पर 22,993 करोड़ रुपए का सकल कर-राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है जिसकी तुलना में इस वर्ष के संशोधित अनुमानों से 20,946 करोड़ रुपए की राशि परिकल्पित की गई है। अनुमान है कि 1984-85 में करों में राज्यों का हिस्सा चासू वर्ष के 5,248 करोड़ रुपए के मुकाबले, 5,739 करोड़ रुपए का होगा और इस प्रकार इसमें लगभग 500 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इस प्रकार, केन्द्र का निवल नर-राजस्व, चासू वर्ष के 15,700 करोड़ रुपए की तुलना में, 17,254 करोड़ रुपए का होगा। रेलवे और डाक-तार से प्राप्त होने वाला लाभ, 1983-84 के संशोधित अनुमानों की अपेक्षा 106 करोड़ रुपए अधिक होगा। सरकारी क्षेत्र के

उपयोगों और राज्य सरकारों से व्याज की अदायगी और ऋणों की वापसी अदायगी के रूप में पहले से अधिक राशि प्राप्त होगी।

62. बाजार ऋणों से चालू वर्ष के 4,000 करोड़ रुपए के मुकाबले, अगले वर्ष 4,100 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। अन्य बचतों के संग्रह की राशि चालू वर्ष के 2,200 करोड़ रुपए के मुकाबले, 2,400 करोड़ रुपए आंकी गई है। वापसी अदायगी की राशि को घटाने के बाद, निवल विदेशी सहायता की राशि चालू वर्ष के 1,902 करोड़ रुपए की तुलना में अनुमानित: 2,089 करोड़ रुपए की होगी। अगले वर्ष के बजट में उस राष्ट्रीय जमा योजना से प्राप्त होने वाली 200 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल की गई है जिसका उल्लेख मैंने अपने भाषण में पहले किया है। इन प्राप्तियों और प्राप्तियों में होने वाली अन्य घट-बढ़ को हिसाब में लेने के बाद, अनुमान है कि 1984-85 में कुल 40,501 करोड़ रुपए की प्राप्तियों होगी। इन प्राप्तियों में रेलवे के यात्री किराए और मास-भाड़े में किए गए परिवर्तनों के प्रभाव को हिसाब में ले लिया गया है। कुल अनुमानित व्यय 42,536 करोड़ रुपए का होगा। इस प्रकार बजट में कराधान की मौजूदा दरों पर कुल मिलकर 2,035 करोड़ रुपए का बाटा रहेगा।

63. मैंने सदन का काफी समय ले लिया है। अब मैं अन्य कर प्रस्तावों की ओर आता हूँ।

(भाग ब)

64. इन प्रस्तावों को तैयार करते हुए, मैंने प्रारंभिक स्थिति की उन वास्तविकताओं को ध्यान में रखने को कोशिश की है, जिनका उल्लेख मैंने अपने भाषण के शुरू में किया था। मुझे आशा है कि ऐसा करते समय मैंने उस विशिष्ट प्राणामी घटना को पूर्णतः अनदेखा नहीं किया है, जिसका संभव है हम सब लोगों के लिए बड़ा महत्व है।

65. अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रस्ताव नियम-भिन्न आय-कर के क्षेत्र के बारे में है। मेरा वैयक्तिक कराधान की दरों के समूचे ढांचे में व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव है। 15,001 रुपए से 20,000 रुपए तक की कर-योग्य आय के पहले खंड पर कर की मौजूबा दर 25 प्रतिशत है। सदन को याद होगा कि पिछले वर्ष इस दर को उस समय विद्यमान 30 प्रतिशत के स्तर से घटा कर नीचे किया गया था। अब मैं इस दर को और घटा कर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। 20,000 रुपए से ऊपर के सभी आय-स्तरों पर भी राहत दी गई है। 1 लाख रुपए से ऊपर की आमदनियों पर कर की अधिकतम सीमांतिक दर को 60 प्रतिशत से घटा कर 55 प्रतिशत किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, कुछ छंडों पर कर की नई दर इस प्रकार होगी: 25,001 रुपए से 30,000 रुपए तक के आय-खंड पर नई दर 35 प्रतिशत की मौजूबा दर की तुलना में 30 प्रतिशत, 50,001 रुपए से 60,000 रुपए तक के आय-खंड पर 50 प्रतिशत की मौजूबा दर की तुलना में 45 प्रतिशत, और 70,001 रुपए से 80,000 रुपए तक के आय-खंड पर 55 प्रतिशत की मौजूबा दर की तुलना में 50 प्रतिशत होगी।

66. उक्त प्रस्ताव से आय के भी स्तरों पर राहत मिलेगी। मुझे आशा है कि मानक कटौती में पिछले वर्ष की गई दुर्घि के साथ-साथ इस उपाय से विशेष रूप से बंभी आमदनी वाले वर्गों को काफी राहत मिलेगी। संशोधित कर अनुसूची के अनुसार 20,000 रुपए की आद वाले करदाता को कर में 281 रुपए की राहत प्राप्त होगी, जो उसके द्वारा पहले देय कर के 20 प्रतिशत के बराबर है। 30,000 रुपए के आय-स्तर पर यह राहत 844 रुपए अथवा पुराने दर-ढांचे के अंतर्गत देय कर के 16.67 प्रतिशत के बराबर, और 50,000 रुपए की आमदनी के स्तर पर देय कर के 10 प्रतिशत के बराबर होगी।

67. अनुमान लगाया गया है कि करदाताओं की संख्या में और विशिष्ट आय-खंडों की निर्धारित आमदनियों में कोई परिवर्तन न होने पर, प्रस्तावित दर अनुसूची से राजस्व में 180 करोड़ रुपए की हानि होगी। लेकिन कर की दरों को कम करने पर सामान्यतः यह आशा की जा सकती है कि इसके फलस्वरूप विशिष्ट आय-खंडों पर करदाताओं की संख्या में

बृद्धि होगी और कर संबंधी उपबंधों का अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह पालन होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मैंने राजस्व में केवल 59 करोड़ रुपए की निवल हानि होने की परिकल्पना की है। यह हानि पूर्णतः, बंधों, आय वाले वर्गों को कर में दी गई राहत के परिणामस्वरूप हुई मानी जा सकती है। जहां तक व्यापार और व्यवसाय से होने वाली आय का सम्बन्ध है, मेरी यह धारणा है कि दरों में कमी किए जाने से कर संबंधी उपबंधों का अधिक अच्छी तरह पालन करने और आय को अधिक सही रूप में प्रकट करने को प्रोत्साहन मिलेगा और राजस्व में होने वाली कमी इससे अंशतः पूरी हो जाएगी।

68. अध्यक्ष महोदय, एक तरह से इस प्रस्ताव से कर प्रणाली को मुक्तिसंगत बनाने के उस कार्यक्रम को जारी रखा गया है, जो मेरी पार्टी द्वारा 1974 में प्रारम्भ किया गया था, 1976 में आगे बढ़ाया गया था और 1980 में पुनः सत्ता में आने के बाद इसे और बल प्रदान किया गया था। मौजूदा कर ढांचे को एक ऐसे स्तर पर ले आया गया है जिसे मैं यथार्थतापूर्ण और पूर्णतः उचित मानता हूँ मुझे आशा है कि उपयुक्त उपाय का हमारी कर संस्कृति पर हितकारी प्रभाव पड़ेगा और उससे अधिक से अधिक करदाताओं को आगे आने और स्वेच्छा से अपनी सही आय घोषित करने की प्रेरणा मिलेगी।

69. इसके साथ-साथ, कर-प्रशासन को सरल बनाने और उसे कर-दाताओं की जरूरतों के अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए यह जरूरी होगा कि कर-निर्धारण के काम को जहां तक हो सके कम से कम समय में पूरा करने की कोशिश की जाए। जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, संक्षिप्त कर-निर्धारण योजना की परिधि में 1 लाख रुपए तक की आय आ जाती है। इस सीमा के भीतर आने वाली आमदनियों के केवल कुछ प्रतिशत मामलों की ही आज पड़ताल की जाती है, और ऐसे मामलों को यदुच्छिन्न नमूने के आधार पर चुना जाता है। 1983-84 में संक्षिप्त कर-निर्धारण के 85 प्रतिशत कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है। मैंने आय कर विभाग को कर निर्धारण के काम में और तेजी लाने की हिदायत दी है।

70. पिछले कुछ वर्षों से आय-कर अधिनियम में ऐसे उपबन्ध शामिल हैं जिनसे केन्द्रीय सरकार को ऐसी अवसर सम्पत्ति का अधिग्रहण करने की शक्ति प्राप्त है जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपए से अधिक हो। इस शक्ति का प्रयोग ऐसी स्थितियों में किया जा सकता है, जहां सम्पत्ति के अन्तरण का घोषित प्रतिफल (कन्सिडरेशन) उचित बाजार मूल्य से कम हो। अधिक संख्या में अपेक्षाकृत कम मूल्य वाले मामलों को निपटाने में जो अनुत्पादक काम होता है, उससे बचने के उद्देश्य से और बाजार भावों में हुई बृद्धि को देखते हुए, मैंने उक्त उपबन्ध को इस प्रकार संशोधित किया है जिससे कि इस शक्ति का प्रयोग केवल उन मामलों में ही किया जाएगा, जहां उचित बाजार मूल्य 50,000 रुपए से अधिक होगा। इसे और सरल बनाने के लिए यह उपबन्ध किया जा रहा है कि पंजीकरण अधिकारी के समक्ष विहित विवरण केवल उन मामलों में दाखिल किया जाएगा जहां अन्तरण के प्रतिफल का मूल्य 10,000 रुपए की मौजूबा सीमा के स्थान पर 25,000 रुपए से अधिक होगा।

71. मैं समझता हूँ कि दरों में कमी किए जाने और कर निर्धारण शीघ्रतापूर्वक किए जाने से अब उन लोगों के प्रति नरमी दिखाने का कोई बहाना नहीं रहेगा जो हमारे कानूनों का अनुचित लाभ उठाते हैं। ऐसे मामलों के बारे में अनिवार्यतः कड़ाई से कार्रवाई करनी होगी। कर अपवचन और कर-परिवर्जन को हतोत्साहित करने के लिए मैं कुछ और उपाय भी लागू कर रहा हूँ। ऐसे सभी मामलों में, जहां कुछ करोड़ों 20 लाख रुपए से अधिक का हो, अथवा जहां किसी व्यवसाय से हुई सकल प्राप्ति 10 लाख रुपए से अधिक को हो, में लेखाओं की अनिवार्य लेखा-परीक्षा कराने का उपबन्ध कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लेखा पुस्तकें और अन्य अभिलेख उचित रूप से रखे जाएं और उनसे करदाता की वास्तविक आमदनी सही रूप में प्रकट हो। मैं यह भी प्रस्ताव कर रहा हूँ कि 10,000 रुपए अथवा उससे अधिक की उन्नत अथवा जमा राशियों केवल रेबित चेकों या बैंक ड्राफ्टों के

जरिए ही सी या स्वीकार की जाएगी।

72. मैंने देखा है कि आय-कर अधिनियम के मौजूदा उपबन्धों में यह व्यवस्था है कि बेनामी रूप से धारित किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए वैध मालिक होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी न्यायालय में तब तक वाद दायर नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने आय-कर की किसी विवरणी में ऐसी सम्पत्ति से होने, वाली आय अथवा निवल धन को किसी विवरणी में ऐसी सम्पत्ति के मूल्य की घोषणा न कर रखी हो या इस सम्बन्ध में आय-कर अधिकारी को बिलित फार्म में सूचना न दे रखी हो। इस समय ऐसी विवरणी या सूचना वाद दायर करने से पहले कभी भी सी जा सकती है। सम्पत्ति के बेनामी धारण की पद्धति पर रोक लगाने के उद्देश्य से, मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूँ कि अब से सभी मामलों में सम्पत्ति के अर्जन के एक वर्ष के अन्तर-अन्तर आय कर आयुक्त को बिलित फार्म में सूचना देना अनिवार्य होगा। इस संशोधन से विभाग सम्पत्ति के ऐसे बेनामी अर्जन के सम्बन्ध में, अवधि के समाप्त होने से काफी पहले ही, उपयुक्त कार्रवाई शुरू कर सकेगा।

73. निगम-क्षेत्र के बाद अब मैं अपना ध्यान निगम क्षेत्र की ओर लाता हूँ। इस क्षेत्र के लिए कर की दरों में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं एक मुद्दा दे रहा हूँ। पिछले वर्ष, कम्पनियों द्वारा देय अधिभार को 2.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 5 प्रतिशत करते समय मैंने कम्पनियों को अतिरिक्त अधिभार की राशि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जमा कराने का विकल्प दिया था। अब मैं यह उपबन्ध कर रहा हूँ कि कम्पनियाँ इस विकल्प का प्रयोग उनके द्वारा देय अधिभार की समूची राशि के सम्बन्ध में कर सकती हैं। य साधन निगम क्षेत्र के पास वापस लौट आये और आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध होंगे। अपने भाषण के पहले भाग में, मैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नरम शर्तों वाले ऋणों की योजना के अन्तर्गत दिए जा रहे 4 करोड़ रुपये तक के ऋणों के व्याज की दर को घटाने के निर्णय का उल्लेख पहले ही कर चुका हूँ।

74. विभिन्न क्षेत्रों से अप्पावेदन प्राप्त हुए थे कि प्रबन्धकीय पारि-श्रमिक की कटौतीयोग्य राशि की जो सीमा आय-कर अधिनियम में निर्धारित है। वह कम है और उसे बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे सच को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रबन्धकीय पारिश्रमिकों में जो परिवर्तन किए गए हैं उन्हें देखने हुए, मैं भी प्रबन्धकों के वेतन की उच्चतम सीमाओं को 5,000 रुपये से बढ़ा कर 7,500 रुपये प्रति मास कर रहा हूँ लेकिन परिनिष्ठियों से सम्बन्धित उच्चतम सीमा अपरिवर्तित रहेगी।

75. चाय के उत्पादन और विनिर्माण का कारोबार करने वालों के लिए भी कुछ रियायतों की व्यवस्था की जा रही है। मौजूदा उपबन्धों में चाय की झाड़ियों के पुनः रोपण अथवा प्रतिस्थापन के लिए प्राप्त आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में ही कर से छूट की व्यवस्था है। मैं कर को इस छूट को इन क्षेत्रों के कार्याकर्ता और उत्पन्न की अन्य अनुमोदित योजनाओं के लिए प्राप्त आर्थिक सहायता पर भी लागू कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि इस उपाय से चाय के उत्पादन को बढ़ाने की हमारी योजना को मदद मिलेगी।

76. मुझे विश्वास है कि मेरे अगले प्रस्ताव का स्वागत बहुत अधिक लोगों द्वारा किया जाएगा। इस समय निवेशकर्ता ऋणपत्रों पर व्याज और लाभांश, जोड़ पर कर की कटौती कराए बिना, प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे आय-कर अधिकारी से लिया गया छूट प्रमाण-पत्र भर कर दे या इस आशय का एक घोषणा-पत्र दाखिला कर दें कि उस वर्ष उनकी आय छूट की सीमा से नीचे है। कागजी कार्रवाई को कम करने और छोटे निवेश-कर्तवियों को अमुविधा से बचाने के लिए मैं यह उपबन्ध करने का प्रस्ताव करता हूँ कि अब से बहुजनधारित कम्पनियाँ ऋण-पत्रों के व्याज और लाभांश आय की 1,000 रुपये तक की राशि की अवयगी जोत पर कर

की कटौती किए बिना कर सकती हैं, बशर्त कि अवयगी शाहजोग (अकाउंट पेई) चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जाए।

77. अध्यक्ष महोदय, मेरे देखने में आया है कि कराताओं का एक वर्ग कर कानूनों के कतिपय उपबन्धों का दुरुपयोग कर रहा है। पिछले वर्ष मैंने पूर्ण और धार्मिक न्यायों और संस्थाओं के कराधान के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा की थी। मैंने देखा है कि वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा न्यास निधियों के निवेश की जो पद्धति निर्धारित की गई थी, कुछ न्यास उसका पालन नहीं कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ऐसे सभी न्यास और संस्थाएँ निर्धारित निवेश पद्धति का कड़ाई से पालन करें और इस आय अथवा सम्पत्ति का इस्तेमाल व्यवस्थापकों और न्यासियों आदि को लाभ पहुंचाने के लिए न किया जाए। इसलिए मैं दोषी न्यासों और संस्थाओं की आय पर आय कर की अधिकतम सीमास्तिक दर पर कराधान का उपबन्ध करने का प्रस्ताव करता हूँ।

78. मैं इस विषय पर चर्चा करते समय यह उल्लेख करना चाहूंगा कि ऐसे न्यासों की स्थापना करने की प्रवृत्ति देखने में आई है जो कारोबार करने हैं। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ कि जहाँ ऐसे न्यासों को कारोबार से मुनाफा और अधिलाभ हो, वहाँ न्यास की समूची आय पर अधिकतम सीमास्तिक दर से कर लगाया जाएगा; लेकिन जिन मामलों में न्यास की स्थापना वसीयत के जरिए आश्रित सम्बन्धियों के लिए की गई हो, केवल उनमें अपवादस्वरूप ऐसा नहीं किया जाएगा।

79. जो एक अन्य आवांछनीय बात ध्यान में आई है, वह है निगमित निकायों द्वारा तथाकथित कल्याण निधियों में भारी मात्रा में अंशदान करने की प्रवृत्ति मुझे यह भी पता चला है कि इन निधियों का उपयोग मनुष्यों से किया जाता है और इन पर कोई अनुशासन लागू नहीं होता। अतः मैं यह उपबन्ध कर रहा हूँ कि केवल कानून के अन्तर्गत स्थापित की गई निधियों अथवा किसी अनुमोदित भविष्य निधि, अधिवाचिकी की निधि अथवा उपदान निधि में किए जाने वाले अंशदानों के सम्बन्ध में ही कटौती उपलब्ध होगी। मैं यह परिवर्तन भूतलक्षी प्रभाव से कर रहा हूँ ताकि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सके।

80. पिछले वर्ष मैंने निर्यात कारोबार से सम्बन्धित योजना को उबार बना दिया था। मेरा इसे जारी रखने और कुछ अधिक लंबी अवधि तक इसके कार्यचालन पर नजर रखने का विचार है।

81. पिछले वर्ष मैंने उन विभिन्न प्रकार की छूटों और कटौतियों का भी उल्लेख किया था, जो समय पाकर हमारी कर-प्रणाली का अंग बन गई हैं। यद्यपि यह हो सकता है कि प्रत्येक कटौती का अपने आप में कोई लाभ हो, लेकिन कुल मिला कर इनका परिणाम यह हुआ है कि कर प्रणाली बढ़ा पेचीदा हो गया है और कर-परिवर्तन अथवा कर-अनवरण तथा मुकदमेबाजी के रास्ते खुल गए हैं। इसलिए मैंने इनकी समीक्षा करने और जहाँ आवश्यक हो वह ऐसी रियायतों को समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की थी, जिनकी अब कोई उपयोगिता न रही हो। मेरा इस प्रक्रिया की और आगे बढ़ाने का इरादा है।

82. हमारा अनुभव यह है कि व्यय पर आधारित रियायत के परिणामस्वरूप व्यय को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की प्रवृत्ति बन जाती है और इसलिए हमारी कर-प्रणाली में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत उपलब्ध सारी धारित कटौतियों को वापस ले लिया जाए। वास्तविक रूप में किए गए व्यय को कटौती के लिए निस्संदेह अर्हता प्राप्त होती रहेगी। केवल सारांश (वेजेज) का लाभ अब प्राप्त नहीं होगा।

83. मैं आय-कर अधिनियम की धारा 33ब, 35ग, 80ग 80घ और 80ड के अन्तर्गत उपलब्ध छूटों को भी वापस ले रहा हूँ। इस बात के बावजूद कि इन कटौतियों के उद्देश्य ऊपरी तौर पर बड़े प्रशंसनीय हैं, इनका दुरुपयोग किया जाता रहा है अथवा इनसे केवल कुछ ही लोगों

की लाभ पहुँचा है। इनसे संबंधित राजस्व की राशि बड़ी मामूली है। मैं धारा 80उ, 80ड और 80ण, के अन्तर्गत उपलब्ध छूट की मात्रा में भी कमी कर रहा हूँ।

84. अब मैं धन-कर अधिनियम के सम्बन्ध में कुछ रियायतों की घोषणा करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि सम्मानित सदस्य यह सुन कर प्रसन्न होंगे कि किसी एक करदाता के स्वामित्व वाले एक मकान के सम्बन्ध में छूट की मौद्रिक सीमा को 1 लाख रुपए के मौजूदा स्तर से बढ़ा कर 2 लाख रुपए किया जा रहा है। बाजार मूल्यों में हुई वृद्धि देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। मैं विशिष्ट विनियम परिमर्षणियों के संबंध में छूट की सीमा को भी 1,65,000 रुपए के वर्तमान स्तर से बढ़ा कर 2,65,000 रुपए करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ। भारतीय युनिट ट्रस्ट के यूनिटों के संबंध में उपलब्ध 35,000 रुपए की पृथक छूट के साथ, जिसका विस्तार राष्ट्रीय जमा योजना के अन्तर्गत जमा-राशियों पर किए जाने का प्रस्ताव है, विशिष्ट विनियम परिमर्षणियों के मूल्य के संबंध में समय छूट की मौजूदा 2 लाख रुपए की अधिकतम सीमा बढ़ा कर 3 लाख रुपए हो जाएगी। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि मैंने अपने भाषण के पहले भाग में विनियम परिमर्षणियों के रूप में बचत गुटाने में हुई सफलता का जिक्र किया था; मुझे आशा है कि इस परिवर्तन में उनमें और वृद्धि होगी।

85. प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में मेरे द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन अपेक्षाकृत मामूली किस्म के हैं और मैं उनके विस्तार में जा कर इस सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता।

86. कतिपय रियायतों को वापस लेने अथवा उनमें फेर-बदल करने के फलस्वरूप राजस्व में जो वृद्धि होगी उसे हिस्सा में लेने के बाद, धायकर से सम्बन्धित मेरे प्रस्तावों से 75 करोड़ रुपए की निवल हानि होगी, जिसमें केन्द्र को 36.32 करोड़ रुपए और राज्यों को 38.68 करोड़ रुपए की हानि होगी।

87. अध्यक्ष महोदय, अब मैं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अपने प्रस्तावों की चर्चा करूँगा। यह मेरा मुख्य उद्देश्य कुछ सोच विचार कर चुने हुए क्षेत्रों में उत्पाद-शुल्कों में यथेष्ट रहित और टैरिफ समायोजनों के जरिए भारतीय उद्योगों के विकास को और बढ़ावा देना है। इसके अलावा, मैंने उपभोक्ताओं के लिए कुछ मर्दों की कीमतों को घटाने और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित रखने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा है। मुझे विश्वास है कि सम्मानित सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं होगी, यदि ऐसा करने हुए मैंने थोड़ा सरकारी राजस्वों का भी ध्यान रखा है।

88. सीमा शुल्कों में संबंधित मेरा प्रमुख प्रस्ताव सहायक सीमा-शुल्कों के बारे में है। 1973 के बजट में वार्षिक आधार पर लगाए गए शुल्क को 31 मार्च, 1983 तक लागू रखने का प्रस्ताव है। मैं कुछ अपवादों के साथ, वर्तमान प्रभावी दरों में 5 प्रतिशतांशों की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं उर्वरकों जैसी आवश्यक मर्दों, केरोसीन तथा हार्ड स्प्रीड डीजल तेल जैसे खुले पेट्रोलियम उत्पादों और अख्तियारी कागज को भी इस प्रस्तावित वृद्धि से अलग रखना चाहता हूँ। इन प्रस्तावों का विस्तृत औपचारिक बजट पत्रों में उपलब्ध है। इस प्रस्ताव से एक पूरे वर्ष में 241.73 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

89. कूड़ पेट्रोलियम पर 9.50 रुपए प्रति मेट्रिक टन के हिस्सा से इस समय जो सीमाशुल्क लग रहा है (जो सहायक शुल्क के रूप में लिया जा रहा है) उसकी यह दर 1973 में निर्धारित की गई थी। पेट्रोलियम उत्पादों की आंतरिक कीमतों पर कोई प्रभाव डाले बिना, मैं कूड़ पर लगने वाले शुल्क को बढ़ाकर 100 रुपए प्रति मेट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस उपाय से राजस्व में 132.76 करोड़ रुपए का फायदा होगा। शुल्क की इस वृद्धि को कम्पनियाँ स्वयं सह लेगी और 1513 GI/83—2

उन्हें इसकी वजह से उपभोक्ता कीमतों में कोई वृद्धि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

90. लोहे और इस्पात की मर्दों पर आयात-शुल्क की वर्तमान दरें कुछ समय पहले तब की गई थी और इस समय वे स्वदेशी उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रही हैं। मैं लोहे और इस्पात (स्टेनलेस स्टील में भिन्न) की भिन्न-भिन्न मर्दों पर बुनियादी सीमा शुल्क में, शुल्क की मौजूदा दरों को दृष्टिगत रखते हुए, 5 प्रतिशतांशों अथवा 10 प्रतिशतांशों की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि स्टेनलेस स्टील की सेटिंग स्कैप पर, जो इस समय सीमाशुल्क से मुक्त है, कुल मिलाकर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से सीमाशुल्क लगा दिया जाए इन उपायों से 84.20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

91. मैं भिन्न कागजों तथा उनके हिस्सों, मेन्टैटिक टैगों और पेट्रोलियम की विशिष्ट वस्तुओं, अर्थात् पेट्रोलियम जेली, सोडियम पेट्रोलियम मन्कोनेट और विभिन्न पैराफीन पर आयात-शुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन प्रस्तावों का औसत बजट पत्रों में उपलब्ध है। इन प्रस्तावों से कोई 5.32 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी।

92. रस्तों और आभूषणों के महत्वपूर्ण क्षेत्र में नियतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, यह प्रस्ताव किया जाता है कि रस्तों और आभूषणों का प्रसंस्करण और विनिर्माण करने वाली कई-गक मशीनों पर लगने वाले सीमाशुल्क की मौजूदा दरों को घटा कर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए। रस्ते प्रसंस्करण मशीनों से प्रसंस्करण की प्रक्रिया में होने वाली हानि बहुत कुछ घट जाएगी और उतने कुल मिलाकर उनकी गुणवत्ता (क्वालिटी) और उत्पादकता बढ़ जाएगी। इस प्रकार, मैं यह प्रस्ताव भी करता हूँ कि खाद्य वस्तुओं के पैकेज बनाने में इस्तेमाल में आने वाली और मान तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा काम में ली जाने वाली विविध मशीनों पर लगने वाले सीमाशुल्कों की मौजूदा दरों को घटा कर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए। आशा की जाती है कि इससे मूल्य योजित रूप में और खुले रूप की बजाए उपभोक्ता पैकों में खाद्य वस्तुओं के नियत को प्रोत्साहित मिलेगा उपर्युक्त प्रस्तावों से कोई 5.24 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

93. मशीनी औजार प्रोद्योगिकी में उत्पत्ति हो जाने के कारण, परंपरागत मशीनी औजारों के स्थान पर सी०एन०सी० मशीनों का प्रयोग अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनकी उत्पादकता अधिक होती है और वे अधिक सटीक होती हैं। मैं सी०एन०सी० प्रणालियों पर लगने वाले सीमा-शुल्क को घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि स्वदेशी मशीनी विनिर्माता सी०एन०सी० मशीनी औजारों की प्रतियोगितात्मक दरों पर वे सकें। इससे 0.82 करोड़ रुपए तक के राजस्व का त्याग करना होगा।

94. कागज उद्योग को उसकी कच्ची सामग्री उचित कीमतों पर सुलभ करने के लिए और अपने अन्य माश्रनों पर बचाव को कम करने के लिए, मैं कागज या गन्ना बनाने के काम आने वाली लुग्दी बनाने के लिए लकड़ी की खपतियों को सीमाशुल्कों से पूरी तरह मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि कागज बनाने के लिए आयात की गई लकड़ी की लुग्दी पर शुल्क को मौजूदा स्तर से घटा कर 30 प्रतिशत कर दिया जाए। ऐसा करने से 1.10 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

95. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंशकरण भावि विषयों से संबंधित उपबंधों में और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपबंधों में कुछ परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों का व्यापक बजट-पत्रों में दिया गया है।

96. महोदय, अब मैं उत्पादशुल्कों संबंधी अपने प्रस्तावों की और आना हूँ। मेरे इन प्रस्तावों के मुख्य उद्देश्य हैं: मुद्रास्फीति के प्रभावों को स्थूलतः कराना, कर परिवर्तन और अपवर्धन की गुंजाइश को कम

करता, मांग की मंदी से प्रभावित होने हुए उद्योगों को सहारा देना और पहले से निर्मित क्षमता तथा निवेश का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना।

97. मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विशेष उत्पाद-शुल्क मौजूदा दरों पर और वर्तमान छूटों के साथ 31 मार्च, 1985 तक लागू रहें।

98. राहत से संबंधित मेरा पहला प्रस्ताव खांडमारी चीनी के बारे में है। मैं खांडमारी को चीनी की पूरी तरह उत्पाद-शुल्क से मुक्त करना चाहता हूँ। इस उद्योग के श्रम-प्रधान स्वरूप को देखते हुए और इस उद्योग में रोजगार की वृद्धि के और श्रमरत मुमकिन करने के लिए मैं यह छूट दे रहा हूँ। उत्पाद-शुल्क हटा दिए जाने से, यह उद्योग गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने की अच्छी कीमत दे सकेगा, और इससे दूर-दराज के देशाती इलाकों में स्थित अनेकों खांडमारी के एककों को राहत मिलेगी। इस प्रस्ताव के कारण 16.42 करोड़ रुपए के राजस्व का त्याग करना पड़ेगा। मुझे यह बताया गया है कि खांडमारी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। यदि इस उपाय के फलस्वरूप, देशवासियों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो मैं आशा करता हूँ कि इसका श्रेय, मेरे प्रतिष्ठित सहायोगी स्वास्थ्य मंत्री महोदय को तभी, बल्कि मुझे मिलेगा।

99. सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि 1978 के बजट में बिजली पर उत्पाद-शुल्क, राजस्व के उपाय के रूप में, लगाया गया था। बिजली पर प्राप्त होने वाले शुल्क की सारी निवल राशि राज्यों में वितरित कर दी जाती है। बिजली पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क का समाप्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है और यह राज्य सरकारों पर छोड़ा जा रहा है कि वे जहाँ तक चाहें और जिस तरीके से चाहें, इस भौत का उपयोग कर लें। इससे राज्यों का साधन जुटाने का एक और क्षेत्र मिल जाएगा। मैं राज्यों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कुछ समय दे रहा हूँ। उत्पाद-शुल्क हटाने का यह प्रस्ताव 1 अक्टूबर, 1984 से प्रभावी होगा।

100. कपड़े को सस्ता करने के उद्देश्य से मैं कपड़ा उद्योग को भी काफी राहत देना चाहता हूँ। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि 1982 और 1983 के बजटों में पालिएस्टर के वांछनीय अनुपातों के साथ मिश्रित किस्मों के कपड़े के उत्पादन को प्रोत्साहित दिया गया था। ऐसे कपड़े अधिकारिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इस उद्योग को और राहत देने के लिए और ऐसे कपड़ों की मस्ती कीमतों पर सुलभ करने के सर्वोपरि उद्देश्य से, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि 40 प्रतिशत में अधिक किन्तु 70 प्रतिशत से कम मात्रा में पालिएस्टर वाले पालिस्टर-काटन ब्लैंडेड यार्न पर लगने वाले कुल उत्पाद-शुल्क को घटाकर 5 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाए। ऐसे यार्न पर लगने वाले शुल्क की मौजूदा दरें, आमतौर पर, पालिएस्टर-काटन मिश्रण के अनुपात के आधार पर, 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम से 22.5 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच भिन्न-भिन्न होती हैं। मेरे प्रस्ताव के अंतर्गत 40 प्रतिशत में अधिक किन्तु 70 प्रतिशत से कम मात्रा में पालिएस्टर के सभी मिश्रणों पर उन्नीस टक्के दर से शुल्क लगेगा। पालिएस्टर और विस्काय के इसी प्रकार के मिश्रणों पर उत्पाद-शुल्क घटाकर 10 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया जाएगा। जबकि शुल्क की वर्तमान दरें आमतौर पर 11.25 रुपए प्रति किलोग्राम से 22.50 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच भिन्न-भिन्न होती हैं। इन परिवर्तनों से एक पूरे वर्ष में अनुमानतः 33.25 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

101. मेरा ध्यान मिश्रित कपड़ों (ब्लैंडेड फेब्रिकस) की ओर भी गया है। पालिएस्टर मिश्रित सूती कपड़ों पर, जिनमें पालिएस्टर की मात्रा 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 70 प्रतिशत से कम हो, उत्पाद-शुल्क को घटाकर 2 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाएगा। ऐसे कपड़ों पर इस समय 7.5 प्रतिशत से 17.8 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न दरों पर मूल्यानुसार उत्पाद-शुल्क लगता है। इस दरियायत से एक पूरे वर्ष में राजकोष को 26.50 करोड़ रुपये कम प्राप्त होंगे। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि यह 2 प्रतिशत मूल्यानुसार का शुल्क बिस्की-कर के एज में अनिश्चित

उत्पाद-शुल्क के रूप में वसूल किया जाए। जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम ही है, वस्त्रों पर लगने वाले अनिश्चित उत्पाद-शुल्क की प्राप्तिवा राशियों को मिलती है।

102. पालिएस्टर मिश्रित सूती यार्न और पालिएस्टर मिश्रित सूती कपड़ों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क के ढाँचे में किए जाने वाले इन परिवर्तनों से, 67:33 के अनुपात वाले मिश्रण के मामले में लगभग 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की थोक कीमत वाले और 35 रुपए से 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की खुदरा कीमत वाले कपड़े पर शुल्क में लगभग 3.30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की कमी होगी। इस प्रकार शुल्क कम किए जाने से कपड़ा उद्योग ऐसे कपड़ों को कम कीमतों पर बेच सकेगा।

103. मैं सूती कपड़ों पर भी राहत देने का प्रस्ताव करता हूँ जिनका देश में कपड़े के कुल उत्पादन में अब भी काफी बड़ा हिस्सा है। मैं 51 से कम काउंट वाले और 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक के निर्धारणीय मूल्य के सूती कपड़ों पर उत्पाद-शुल्क में कमी करने का प्रस्ताव करता हूँ। सम्मिश्रित (कंपोजिट) मिलाई के मामले में, ऐसे कपड़ों पर इस समय 2.38 प्रतिशत से 3.56 प्रतिशत तक की भिन्न-भिन्न मूल्यानुसार दरें पर उत्पाद-शुल्क लगता है। पावरलूम और हैडलूम के कपड़ों का संसाधन करने वाले स्वाधीन संसाधकों के मामले में शुल्क की दरियायती दर लागू होती है। मे स्वाधीन संसाधकों द्वारा संसाधित उपयुक्त किस्मों के हैडलूम और पावरलूम के कपड़ों को पूरी तरह शुल्क-मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। सम्मिश्रित मिलाई के कपड़ों के लिए शुल्क की दर को भी घटाकर 1 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है और इस प्रकार स्वाधीन संसाधकों और सम्मिश्रित मिलाई के बीच की मौजूदा अंतर को लगभग कायम रखा जा रहा है। यह शुल्क बिस्की-कर के एज में लगने वाले अनिश्चित उत्पाद-शुल्क के रूप में होगा और यह पूरा का पूरा राज्यों को मिलेगा। ऐसे कपड़े अधिकतर समाज के कमजोर वर्गों के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। शुल्कों में की जाने वाली इस कमी का फायदा यह होगा कि इन वर्गों के लोगों को यह कपड़ा सस्ती कीमतों पर मिलेगा। सूती कपड़ों से संबंधित इस प्रस्ताव से 28.40 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

104. मैं आशा करता हूँ कि मेरे प्रस्तावों से कपड़ा उद्योग को भी मदद मिलेगी। कपड़ों की कीमत कम हो जाने की वजह से उनकी मांग बढ़ेगी और इस प्रकार उद्योग को फायदा पहुँचेगा।

105. ग्राम रील हैंकों के रूप में सूती यार्न और सेल्युलॉसिक स्पन यार्न का इस्तेमाल हाथकरघा क्षेत्र में बराबर बढ़ता जा रहा है। 'हाथकरघा क्षेत्र' में, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पंजीकृत हाथकरघा सहकारी समितियों अथवा हाथकरघों के विकास के लिए स्थापित या अनुमोदित संगठनों को सप्लाई किए जाने वाले ऐसे यार्न पर शुल्क-भार में लगभग 50 प्रतिशत की कमी कर दी जाए। इससे एक पूरे वर्ष में राजकोष को 3 करोड़ रुपए की हानि होगी।

106. कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रस्तावों से जो राजस्व की हानि होगी उसको कुछ हद तक पूरा करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर से अधिक के निर्धारणीय मूल्य के मानव-निर्मित कपड़ों पर बिस्की-कर के बबले में लगने वाले अनिश्चित उत्पाद-शुल्क की दर को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए। यह वृद्धि उन मिश्रित कपड़ों के मामले में लागू नहीं होगी जिनके बारे में शुल्क कम किया जा रहा है। इसका असर उन अधिक कीमती कपड़ों पर पड़ेगा जिनका इस्तेमाल मुख्यतः समाज के अपेक्षाकृत अधिक सम्पन्न वर्गों द्वारा किया जाता है। उन्हें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। इस उपाय से, राजकोष को एक पूरे वर्ष में 27 करोड़ रुपए मिलेंगे और यह राशि भी राज्यों के हिस्से में जाएगी।

107. मैं शोडी कम्बलों और सम्मिश्रित मिलाई द्वारा संसाधित शोडी यार्न से बने ऐसे ही अन्य कम्बलों पर लगने वाले शुल्क में लगभग 7 प्रतिशत की कमी करने का प्रस्ताव करता हूँ। यदि ऐसे शोडी कम्बल स्वाधीन संसाधकों द्वारा संसाधित किए जाएंगे तो उन पर शुल्क में पूरी छूट दी

जाएगी। इस प्रस्ताव से एक पूरे वर्ष में 1 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

108. एक अन्य उद्योग जिस पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है, वह कागज उद्योग है। यह उद्योग कच्ची सामग्री और अन्य निविष्टियों की बढ़ती हुई लागत के कारण एक कठिन दौर से गुजर रहा है। मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य कागज और गत्ते (पेपर बोर्ड) के उत्पादन को प्रोत्साहित देना और दुर्लभ प्राकृतिक वन्य साधनों की रक्षा करना है। मैं कागज बनाने के लिए लकड़ी की खपत्तियों और लकड़ी की लुग्दी के आयात पर सीमा-शुल्क से प्रस्तावित छूट का पट्टे ही उल्लेख कर चुका हूँ। राहत देने के एक और उपाय के रूप में, मैं छापाई तथा लिखाई के कागज और कागज की बड़ी मिलों द्वारा उत्पादित क्राफ्ट पेपर पर भी बुनियादी उत्पाद-शुल्क में 425 रुपए प्रति मेट्रिक टन की कमी करने का प्रस्ताव करता हूँ; और ऐसे कागज पर लगने वाले शुल्क में तबतक रिमायन दी जाएगी यदि उसका बानन में अपरम्परागत कच्ची सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया होगा। इसी के साथ ही अनुसूचित अपरम्परागत कच्ची सामग्रियों की श्रेणी का भी विस्तार किया जा रहा है।

109. इस समय गत्ते के मामले में अपरम्परागत कच्ची सामग्रियों के इस्तेमाल के लिए कोई रिमायन उपलब्ध नहीं है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कम से कम 50 प्रतिशत अपरम्परागत कच्ची सामग्रियों से बने गत्ते पर लगने वाले बुनियादी उत्पाद-शुल्क को, 10 प्रतिशत मूलानुसार + 1430 रुपए प्रति मेट्रिक टन के बतमान सामान्य स्तर से घटाकर 560 रुपए, 900 रुपए अथवा 1120 रुपए प्रति मेट्रिक टन कर दिया जाए जो इस बात पर निर्भर करे कि ऐसी कागज की मिलों ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कागज और गत्ते की निकासी क्रमशः 3,000 मेट्रिक टन, 7,500 मेट्रिक टन अथवा 16,500 मेट्रिक टन से अधिक नहीं हुई थी। अपरम्परागत कच्ची सामग्रियों का इस्तेमाल करने वाले बड़ी कागज मिलों के लिए गत्ते पर लगने वाले बुनियादी उत्पाद-शुल्क की दर को घटाकर 7 प्रतिशत मूलानुसार + 925 रुपए प्रति मेट्रिक टन किया जा रहा है।

110. कागज उद्योग से सम्बंधित मेरे प्रस्तावों से उत्पाद-शुल्कों में एक पूरे वर्ष में 33 करोड़ रुपए की हानि होगी। लकड़ी की खपत्तियों और लकड़ी की लुग्दी के आयात पर प्रस्तावित सीमा-शुल्क संबंधी छूटों के साथ मिलकर इन प्रस्तावों से, आशा है, स्वदेशी कागज उद्योग को विकास का यथेष्ट राजकोषीय समर्थन मिलेगा और उचित कोमतों पर कागज की उपलब्धता बढ़ेगी।

111. सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि कनिष्व विनिर्दिष्ट वस्तुओं के मामले में, अक्टूबर, 1983 में कुछ समय-बद्ध रिमायनों दी गई थी। उस उपाय के प्रति, जो बुद्धिशील मांग को पैदा करके उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य में किया गया था, उद्योग की प्रतिक्रिया को देखते हुए, मैं इस रिमायन को, कुछ परिवर्तनों के साथ, एक वर्ष के लिए जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

112. वाणिज्यिक वाहनों और तीन-गुप्त बाल वाहनों के मामले में, रिमायन को जारी तो रखा जाएगा, लेकिन अक्टूबर, 1983 में शुल्क में दी गई रिमायन को मात्रा में 2-1/2 प्रतिशतों की कमी की जा रही है। मैं कुछ हल्के वाणिज्यिक वाहनों के माइनों को छूट के व्याप्ति-क्षेत्र से हटाने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि उत्पाद-शुल्क की दर के मामले में ऐसे वाहनों के सभी माइनों में समानता आ जाए। इन प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में 45 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

113. मैं रेफ्रिजरेटर्स, डीप फ्रीजर्स और प्रयोगिक उपसाधनों के हिस्सों आदि, स्टोरेज बैटारियों और धरेलु बिजली के उपसाधनों के मामले में दी गई रिमायनों को आगे भी जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। इन सब मदों के कारण राजस्व में कुल मिलाकर कोई 19 करोड़ रुपए की हानि होगी।

114. बसों तथा ट्रकों के टायरों और सड़क-भिन्न प्रयोजनों के लिए जाम में आने वाले टायरों के मामले में, अक्टूबर, 1983 में दी गई

रिमायन को जारी रखने का मेरा विचार नहीं है क्योंकि इस उद्योग द्वारा घोषित मूल्य-वृद्धियों को ध्यान में रखते हुए इस रिमायन को आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी, शुल्क पद्धति को सुव्यवस्थित बनाने के एक उपाय के रूप में और कर-अपवर्जन की गुंजाइश को कम करने के विचार से मेरा मूलानुसार शुल्क दरों के स्थान पर अधि-कीमत: मात्रानुसार शुल्क दरें अपनाए जाने का प्रस्ताव है।

115. चीनी मिट्टी और पॉलिमर के बने खाने-पीने के बर्तनों (टेबलवेयर) के उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों में गतिरोध के आसार दिखाई दे रहे हैं और उद्योग की क्षमता के उपयोग में कमी हो रही है। इस उद्योग को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, मैं इन मदों पर लगने वाली बुनियादी उत्पाद शुल्क की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे राजस्व में 1.5 करोड़ रुपए की हानि होगी।

116. गर्म का मोम ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं माननीय सदस्यों के मित्राज को उठा रखने में उनकी सहायता करना चाहूंगा। मैं टेबल फर्नीचर के मामले में बुनियादी उत्पाद-शुल्क को 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करने और उन सीलिंग फर्नीचर के मामले में, जिनका व्यास 107 से 100 से ज्यादा न हो, 15 प्रतिशत से घटा कर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं डेक्रेट कूलर्स सहित वाष्पणिक कूलर्स पर बुनियादी उत्पाद-शुल्क की 40 प्रतिशत की मूलानुसार दर को घटाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन प्रस्तावों से राजस्व में 5.10 करोड़ रुपए की हानि होगी।

117. शुल्कों को सुव्यवस्थित बनाने के उपाय के रूप में, मैं आबेष्टन तारों के बुनियादी शुल्क को 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत और ताम्बे की तारों की छड़ों के बुनियादी शुल्क में 1300 रुपए प्रति मेट्रिक टन की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। कुल मिला कर, इन परिवर्तनों से राजस्व में न तो हानि होगी और न ही लाभ।

118. प्रैसा कि सम्मानित सदस्यों का याद होगा, बहुत से विख्यात कलाकारों ने एक अपील प्रकाशित की थी जिसमें कला की चोरी (पाइरेसी) को और हथकड़ी ध्यान आकर्षित किया गया था। भूक मैं इन प्रिनिपिड कलाकारों की उम्मीद नहीं कर सकना, इसलिए मैं आवाज मेरे कैमेटों को उत्पाद-शुल्क से पूर्ण रूप से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस सब पर हुई राजस्व हानि मेमेटिक टेपों पर सीमा शुल्क में की गई वृद्धि से लगभग पूरी हो जाने की आशा है।

119. राहत के एक सामान्य उपाय के रूप में मैं खादी और ग्रामीण आयात के एककों द्वारा निर्मित लोडरी साबुन को पूर्ण रूप से उत्पाद-शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ और तकली आपूर्तियों, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों, लालटेनों की कांच की चिमनियों, उच्च कुशलता वाले लकड़ी के स्टोवों, छतरियों और सेब्रीन जैसी आम उपयोग की कतिपय मदों पर उत्पाद-शुल्क को 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन रिमायनों से 1.13 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी।

120. सम्मानित सदस्यों का याद होगा कि उत्पादन-वृद्धि को प्रोत्साहित देने के लिए गत दो वर्षों से एक उत्पाद-शुल्क राहत योजना लागू है। मैं इस योजना को एक और वर्ष के लिए जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

121. सम्मानित सदस्यों को यह भी याद होगा कि पिछले बजट में, मैंने मोहरे और इस्पात की मदों से संबंधित टैरिफ को सुव्यवस्थित बनाया था। इस वर्ष मैंने अलौह धातुओं के मामले में ऐसा ही करने का प्रयत्न किया है। टैरिफ की प्रविष्टियों को अधिक वैज्ञानिक आधार पर संशोधित किया जा रहा है। पिछले वर्ष की भांति इन परिवर्तनों को भी किसी बाध की तारीख से लागू किया जाएगा। तब तक शुल्क की मौजूदा प्रभावी दरें लागू रहेंगी।

122. मैं मिगरेटों पर अनिश्चित उत्पाद-शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। बुनियादी उत्पाद-शुल्क और अनिश्चित उत्पाद-शुल्क के बीच के मौजूदा अनुपात को संशोधित करके उसे 1.75:1 बनाया जा रहा है। इस उपाय के परिणामस्वरूप आयाती वित्त वर्ष में बुनियादी उत्पाद-शुल्क खाते में प्रतिरिक्त उत्पाद-शुल्क खाते में 42.89 करोड़ रुपये अन्तर्लिप्त हो जाएंगे और इस प्रकार राज्यों का प्राप्त होने वाली राशि में वृद्धि हो जाएगी। बुनियादी उत्पाद-शुल्क के अंतर्गत निर्धारित राशि में उतनी ही कमी हो जाएगी। मिगरेटों पर उत्पाद-शुल्कों के कुल भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

123. कुछ अन्य छोटे-मोटे प्रस्ताव भी हैं जिनका राजस्व का वृद्धि से कोई ज्यादा महत्व नहीं है। इनमें, कुछ मामलों में उत्पाद-शुल्कों में पुनः समायोजन करना और कुछ उत टैरिफ मदों की सूची से हटाना शामिल है जिन्हें काफी समय से पूर्णतः छूट प्राप्त है।

124. आय-कर अपील अधिकरण तथा सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के कार्यवाहन में प्राप्त हुए अनुभव का वृष्टिगत रखते हुए, इनसे संबंधित कानूनों में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है। ये संशोधन मुख्यतः प्रशासनिक स्वरूप के हैं। मैं इन प्रस्तावों का वर्णन करके सदन का समय नहीं लेना चाहता।

125. अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों से प्राप्त राजस्व में, जो 1953-54 में लगभग 100 करोड़ रुपए था, असाधारण वृद्धि हुई है और यह बढ़ कर 1983-84 में 10,100 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है, और इसके साथ-साथ केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ में भी काफी वृद्धि हुई है। मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है, जब टैरिफ को युक्ति-संगत बनाने के लिए, जिसमें पिछले तीन दशकों में बहुत वृद्धि हुई है, इसकी व्यापक रूप से समीक्षा की जाए। इसके लिए व्यापक अध्ययन की आवश्यकता होगी। जिसे केवल कोई तकनीकी अध्ययन बल ही अच्छी तरह से कर सकता है। अतः मैं एक ऐसे बल से गठन का प्रस्ताव करता हूँ।

126. मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, उनसे सीमा-शुल्कों के रूप में 465.41 करोड़ रुपए और उत्पाद-शुल्कों के रूप में 33.10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। बुनियादी शुल्क खाते से अतिरिक्त शुल्क (बिन्नी कर के बदले) खाते में 43.64 करोड़ रुपए का अन्तर्लप होना। सीमा-शुल्कों के अंतर्गत कुल मिलाकर 7.26 करोड़ रुपए की रियायतें और राहतें और उत्पाद-शुल्कों के अंतर्गत 222.43 करोड़ रुपए की रियायतें और राहतें दी गई हैं। सीमा-शुल्कों से 458.15 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति होगी। उत्पाद-शुल्कों के अंतर्गत 189.33 करोड़ रुपए की निवल हानि होगी, जिसमें केन्द्र का हिस्सा 148.95 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 40.38 करोड़ रुपए होगा। इसमें बिन्नी-कर के एवज में अतिरिक्त उत्पाद-शुल्कों में राज्यों के 52.31 करोड़ रुपए के हिस्से को भी हिसाब में ले लिया गया है। इन अतिरिक्त कर प्रयत्नों से केन्द्रीय सरकार को पूरे वर्ष में 309.20 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

127. सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों में किए गए परिवर्तनों का पहली मार्च, 1984 से प्रभावी बनाने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियाँ सभा-पटल पर यथासमय रख दी जाएँगी।

128. मैं पहले बता चुका हूँ कि कराधान की मौजूदा बरों पर बजट में 2,035 करोड़ रुपए का घाटा होगा। अब प्रस्तावित कर उपायों और राहतों तथा रियायतों के फलस्वरूप केन्द्र को 272.88 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इससे 1,762 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा, जिसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मेरा यह प्रयत्न रहा है कि बजटीय ढाँचे को अपेक्षाकृत कम रखा जाए और मुझे विश्वास है कि सम्मानित सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इतना घाटा हमारी परिस्थितियों के अनुसार उचित ही है। मुझे आशा है कि इस काम वादे तथा उत्पादन को बढ़ाने और कीमतों को कम करने के मेरे प्रस्तावों का अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर अनुकूल प्रभाव

पड़ेगा। इस अवसर पर मैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह श्लोक उद्धृत करना चाहूँगा :—

एव कुर्यात्समुदयं वृद्धिं वायस्य दर्शयेत्।

होम व्यवस्था न प्राज्ञः साधयेन्न विपर्ययम्॥

129. चार बरों पूर्व, मुझसे पिछले सुप्रसिद्धित वित्त मंत्री महोदय ने इस सरकार का पहला बजट पेश करने समय देश की अर्थव्यवस्था को पहुँची क्षति को दूर करने और उसे स्थिरता, विकास और सामाजिक न्याय के मार्ग पर पुनः प्रतिष्ठापित करने के हमारे दृढ़ विश्वास का उल्लेख किया था। अध्यक्ष महोदय, हमने उस वचन का पालन किया है।

130. महोदय, मैं यह बजट सदन को प्रस्तुत करता हूँ।

ए० रमावारी, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Budget Division)

Budget 1984-85 Speech of Minister of Finance

On 29th February, 1984

New Delhi, the 1st March, 1984

(PART A)

Sir,

I rise to present the Budget for the year 1984-85.

2. The Budget has been formulated against the background of strong recovery in national income and agriculture, and an equally impressive improvement in our balance of payments. These and other developments in the economy have been covered in detail in the Economic Survey, presented to the House a couple of days ago. I shall, therefore, be brief in reviewing the current economic situation.

3. As the House is aware, the country had to go through two years of severe drought and one year of indifferent monsoon during the period 1979-80 to 1982-83. Foodgrains production, which had reached 132 million tonnes in 1978-79, declined to 110 million tonnes in the following year. It recovered to 133 million tonnes in 1981-82 but then declined again to 128 million tonnes in 1982-83 because of another severe drought. The current year has seen a major breakthrough in foodgrains production, and we are not only likely to recover lost ground, but also improve substantially on the previous peak. Foodgrains production in 1983-84 is expected to exceed the target of 142 million tonnes. Agricultural production as a whole is likely to increase by 9 per cent over the previous year. Hon'ble Members will agree that this is convincing testimony to the soundness of our agricultural strategy and to the hard work of our farmers.

4. Industrial performance shows an improvement over the previous year, but the recovery in industrial production still seems weak. Industrial growth in the current year is likely to be about 4.5 per cent, compared with 3.9 per cent in 1982-83. For the four year period after 1979-80, industrial growth will average slightly more than 5 per cent. This is well below the potential of the industrial sector. We must aim at a growth rate of 7 to 8 per cent in industry if we are to maintain high rate of growth of GDP and provide employment for our growing labour force in the years ahead.

5. The national income growth in 1983-84 is likely to be in the range of 6 to 7 per cent. In the four years since the present Government took over, the average growth rate in national income has been about 5.4 per cent which is higher than the rate of growth in the first four years of any previous Plan. Per capita income in this period will have risen at an average rate exceeding 3 per cent per year.

This achievement is all the more noteworthy when viewed against the background of a highly adverse international economic environment, and a severe drought.

6. The years 1981-82 and 1982-83 were characterised by exceptionally low rates of inflation. The annual rate of inflation which had reached a high of 21.4 per cent in 1979-80 was brought down to 16.7 per cent in 1980-81 and further to only 2.4 per cent at the end of 1981-82. The annual rate of inflation at the end of 1982-83 was 6.2 per cent, which is unusually low for a drought year. But, there has been an acceleration in the annual rate of inflation in the current year despite an excellent crop. The initial delay in the arrival of the monsoon and the high liquidity in the economy exerted pressure on prices in the early part of the year. The favourable effects of a good crop led to a decline in cereal prices after harvesting. However, this was largely offset by sharp increases in prices of a few commodities such as pulses, certain edible oils, rubber, tea and cotton because of both domestic and international factors. As a result, the seasonal dip in prices, which normally occurs towards the end of September has been weak.

7. As the House is aware, the Government has taken several measures to minimise the impact of the drought and to contain the price rise. Action was taken to increase procurement, availability, and releases of sensitive commodities such as wheat, sugar, and edible oils through the public distribution system. Steps were also taken to mop up excess liquidity with the banking system and to curtail Government expenditure. Exports of cotton and CTC teas were restrained in order to increase domestic availability. Further measures will be taken as required to ensure that there is no repetition of the experience of 1979-80, when prices were allowed to increase by over 21 per cent.

8. Let me now turn to the external payments situation facing the economy. In my budget speech last year, I had informed the House of the improvement that had taken place in our balance of payment in 1982-83. I am happy to say that this improvement has gained strength in 1983-84. The trade gap, which declined from Rs. 5800 crores in 1981-82 to about Rs. 5500 crores in 1982-83, is expected to decline further in the current year. Receipts on invisibles account have remained buoyant and the incentives for non-resident deposits have been highly successful. Our foreign exchange reserves, inclusive of IMF drawings, have increased by Rs. 662 crores in the current financial year upto 10th February.

9. Our strategy for bringing the balance of payments under control, after the sharp deterioration that occurred in 1979-80, has paid rich dividends. In view of the improvement in our payments position, the Government has voluntarily decided not to avail of the balance of 1.1 billion SDR under the Extended Fund Facility of the IMF. While intervening in the debate on the IMF loan in this House in December, 1981, the Prime Minister had this to say, and I quote :

"It does not force us to borrow, nor shall we borrow unless it is in the national interest. There is absolutely no question of our accepting any programme which is incompatible with our policy, declared and accepted by Parliament. It is inconceivable that anybody should think that we would accept assistance from any external agency which dictates terms which are not in consonance with such policies."

This was true then, and it is true now.

10. Belying the prophecies of doom by many a self-styled Cassandra, the economy has emerged stronger as a result of the adjustment effort mounted by us. None of the dire consequences that we being warned about has occurred. We have not cut subsidies. We have not cut wages. We have not compromised on Planning. We have not been trapped in a debt crisis. We have not faltered in our commitment to anti-poverty programmes or the welfare of our people. We entered into this loan arrangement with our eyes open. We have come out of it with our heads high.

11. We hope that our decision to forgo the balance of the amount available to us under the IMF loan would, in a small way, help the IMF to provide greater assistance to other developing countries. I must take this opportunity to express our appreciation for the goodwill and mutual understanding that has marked our relationship with the IMF during the entire period of the EFF arrangement.

12. However, there can be no room for complacency. We must persist with the policies that have brought about this favourable outcome. It is necessary to work even harder to save imports in critical areas and to increase exports. Our exports, net of oil, in the first seven months of 1983-84 increased by 9.9 per cent. This is a reasonable performance considering that world trade has been stagnant for quite some time. We would need to do even better in the future in order to meet the essential import requirements of a growing economy, and to keep the debt service ratio at a manageable level.

13. The Government has taken several steps in the last four years to mobilise resources for public sector investment, and to increase the rate of public savings for financing the Plan. Apart from adjustment of the tax rates, the fiscal instrument has been used to provide stronger incentives for savings in the form of financial assets. Interest rates on deposits were also revised upwards with the same objective in view. These policies have been highly successful and the inflow of funds in small savings as well as time deposits has exceeded expectations. An important task of fiscal policy in the years ahead is to strengthen this trend.

14. In considering the strategy for resource mobilisation we have to recognise that while our tax rates are relatively high, the tax base is narrow. The evils of black money and tax evasion also have to be reckoned with. The Government is fully committed to come down heavily on tax evaders. At the same time, we must ensure that as far as possible, the tax system itself does not become a source of encouragement for evasion. Simplification and rationalisation of the tax system must, therefore, remain important objectives of our fiscal policy.

15. The Central Public sector enterprises had shown a net profit of Rs. 618 crores in 1982-83. Although a large number of public sector enterprises have continued to show profits in 1983-84, their overall performance has been below expectations. The erosion of profitability was largely due to losses incurred in a few sectors, such as steel and coal. The Government has taken steps to improve their functioning. We must ensure that capital is used more efficiently so that larger resources are available for future expansion.

16. In order to fulfil our social commitments and protect jobs, Government had to take over a large number of sick units and sustain them through injection of fresh resources. While some of them have turned the corner, a large number of them continue to incur losses. The time has come to undertake a careful review of the performance of sick units in the public sector with a view to reducing the drain on our resources. This the Government proposes to do. Economic viability must be the principal test for the survival of an enterprise.

17. The growth of deposits with the banking system in the current year has substantially exceeded their requirements of funds for credit expansion. This has, in the short run, resulted in some excess liquidity with the banking system. In this situation, and in order to mobilise some resources for public investment, it is considered desirable to introduce another financial instrument with broadly the same characteristics as longer term time deposits with banks. Under the scheme, which will be called the "National Deposit Scheme", certificates of deposits with a maturity of four years can be purchased from designated outlets. The investor will have the option to encash these deposits any time after one year. The interest rate will be 10.5 per cent if these deposits are held for four years and 10.9 and 7 per cent if these are held for three, two and one year respectively. Interest from these deposits will be eligible for tax exemption upto the full limit of Rs. 10,000 under Section 80I, of the Income-tax Act. The target of receipts under this scheme is Rs. 500 crores over a

period of time. I should clarify that this is a temporary scheme, and will be discontinued after this target is reached or earlier, if monetary developments so warrant.

18. Pursuant to the recommendations of the High Level Committee on financial institutions set up by the Government last year, it has been decided to make certain changes in the "convertibility clause". In view of the increases in capital costs of projects and the investment limit for the delicensed sector, the threshold for exemption from convertibility clause is being raised from the existing level of Rs. 1 crore to Rs. 5 crores.

19. Further, in the case of non-MRTP companies, convertibility clause will not be stipulated where the holding of equity by all financial institutions in such a company exceeds 26 per cent. In the case of MRTP companies/large houses, however, the existing limit of 40 per cent will continue. In order to encourage investment in "No Industry" district there will be complete exemption from convertibility clause in respect of units proposed to be located in these districts. The functioning of nominee directors of institutions on the boards of assisted companies is also being revamped. Detailed guidelines on these and other related aspects are being issued separately.

20. The Industrial Development Bank of India has been providing liberal financing facilities for modernisation of industry. The IDBI's scheme for this purpose was recently extended to all industrial units and assistance under this scheme upto Rs. 4 crores is being provided at a concessional rate of interest of 12.5 per cent. In order to reduce financing costs of modernisation schemes, it has been decided that the rate of interest under the IDBI scheme for loans upto Rs. 4 crores will be reduced to 11.5 per cent until further notice. Weak units will be provided assistance upto this amount at an even lower rate of interest of 10 per cent.

21. As the House is aware, the Government has been giving consideration to the desirability of a change in the financial year. As I informed the House last year, I invited the views of the State Governments on this proposal. The response has been generally favourable. In order to examine suggestions received from State Governments as well as trade and industry, and to work out the modalities for effecting a change in the financial year, I propose to set up an expert committee, which would include representatives of Central Government, State Governments, Reserve Bank of India, Comptroller and Auditor General and some non-official members. This committee will be requested to submit its report by the end of September, 1984.

22. I shall now turn to the Revised Estimates for 1983-84 and the Budget Estimates for 1984-85.

Revised Estimates for 1983-84

23. The House will recall that the Central sector Plan outlay for 1983-84 was fixed at Rs. 13,870 crores. This was to be financed to the extent of Rs. 8,390 crores from the budget and Rs. 5,480 crores through the internal and extra-budgetary resources of the public sector enterprises. Despite erosion in the internal resources of certain public sector enterprises, it has been my endeavour to ensure that the total Plan outlay during the year is not adversely affected. The Central Plan outlay in 1983-84 is now estimated at Rs. 14,059 crores. This has been made possible by an increase in the budgetary support by Rs. 1,007 crores over the Budget Estimates.

24. Budgetary support for the Posts and Telegraphs Plan has been increased by Rs. 203 crores. The Railway Plan outlay has been stepped up by Rs. 100 crores with an additional budgetary support of Rs. 54 crores. In the Transport and Communications sectors, I have provided additional funds for Space projects like INSAT, and extension of television coverage. To maintain the progress of the Visakhapatnam Steel Plant, the budget provision has been augmented by

Rs. 250 crores. For Chemicals & Fertilizers, the enhanced allocation of Rs. 133 crores is largely due to the fall in internal resources and change in the pattern of financing. In the Energy sector, coal projects get additional funds of Rs. 30 crores to expedite on-going projects. To improve the capital base of the Industrial Development Bank of India, a special provision of Rs. 130 crores has been made. Rupees 110 crores have been set apart for the new rural landless employment guarantee programme launched during the current year. I have also increased the provision for welfare of scheduled castes/tribes and backward classes and important social sectors like health and family welfare.

25. The Central assistance for States' and Union territories' Plan has been increased by Rs. 392 crores from Rs. 4,462 crores to Rs. 4,854 crores. This includes advance Plan assistance of Rs. 190 crores to States affected by failure of monsoon particularly in the first half of the current year. Additional Plan assistance of Rs. 82 crores has been provided to the State of Assam, a large part of which is for relief and rehabilitation of the riot victims in that State.

26. Utmost care has been taken to contain the non-Plan expenditure. There were, however, certain unavoidable commitments. Additional provision of Rs. 400 crores has been made for ways and means advances to State Governments and Technical Credits under rupee-trade agreements. The short-term loans to States for agricultural inputs have been stepped up by Rs. 110 crores. There is an increase of Rs. 300 crores in loans to State Governments, as their share of small savings will be higher on account of higher collections. The second half of the current year witnessed floods, cyclones and hailstorm in as many as 15 States. An additional non-Plan grant of Rs. 150 crores has been provided for the relief of distress on account of these calamities.

27. Further, I am providing additional non-Plan assistance amounting to Rs. 500 crores to States. I shall refer to this later while dealing with the State Plan outlay for next year. Out of this loan of Rs. 500 crores, an amount of Rs. 400 crores would help the States to clear part of their deficits of 1982-83.

28. The provision for Defence has been increased from Rs. 5,971 crores to Rs. 6,350 crores in the Revised Estimates. The interim relief and bonus sanctioned to Government employees in the current year is estimated to cost about Rs. 280 crores in respect of all the departments of the Government. Subsidy on imported and domestic fertilizers will go up by Rs. 250 crores to Rs. 1,048 crores as the consumer price of fertilisers was reduced in June 1983. During the current year, because of financial difficulties, certain public sector undertakings, particularly Heavy Engineering Corporation, National Textile Corporation and Delhi Transport Corporation, will be requiring larger non-Plan assistance than provided in the Budget Estimates. It has also been decided to extend the subsidy scheme for Calcutta Port and Haldia Channel dredging up to the end of next year.

29. Revised Estimates also include additional provision of Rs. 502 crores for subscription towards our higher quota in the IMF. This, however, will have no net impact on the budget as payments for quota subscriptions are matched by corresponding receipts. Taking these and other variations into account, the non-Plan expenditure in the Revised Estimates is placed at Rs. 34,773 crores against the Budget Estimates of Rs. 21,984 crores.

30. Coming to receipts, the Budget Estimates of receipts from income-tax and customs duties are likely to be achieved. Corporation tax receipts will be higher by Rs. 203 crores due to larger payments by oil companies. Union excise duties are also estimated to be Rs. 85 crores higher mainly due to larger collection of cesses on crude oil and coal. The Centre's tax revenue, after paying the States' share of taxes, is estimated at Rs. 15,700 crores as against the Budget Estimates of Rs. 15,460 crores.

31. Under non-tax revenue, the dividend from Railways is likely to be Rs. 127 crores less than the Budget Estimates. This decrease will, however, be more than offset by increases under other heads and total non-tax revenue in the current year is expected to show an improvement of Rs. 130 crores over the Budget Estimates.

32. Under capital receipts, I am happy to inform the House that the net collections under small savings during the current year may amount to Rs. 2,200 crores against the Budget Estimates of Rs. 1,700 crores. This is a welcome response to the incentives provided for small savings in the current year's budget. The repayment of Technical Credits, expected to be Rs. 1,150 crores as against Rs. 800 crores assumed in the Budget. The receipt, net of outgo, will be Rs. 350 crores against the Budget Estimates of Rs. 200 crores.

33. The receipts from special deposits of non-Government provident funds and the like are estimated to be Rs. 190 crores higher than the Budget Estimates. Taking into account the deposits of surplus funds of oil sector, additional coveries of ways and means and short-term advances to the State Governments and other variations, capital receipts in the current year are estimated at Rs. 15,965 crores as against the Budget Estimates of Rs. 12,656 crores.

34. Total receipts are thus estimated to go up from Rs. 33,250 crores to Rs. 36,929 crores. This will leave a budgetary deficit of Rs. 1,695 crores for the current year as against the Budget Estimates of Rs. 1,586 crores. This excludes the special loan assistance of Rs. 400 crores provided to States for clearing their overdrafts at the end of the previous year 1982-83. I am sure the House will agree that despite unavoidable budgetary pressures, we have been able to keep the deficit within prudent limits.

Budget Estimates for 1984-85

35. Hon'ble Members will recall that when our Government took office in January 1980, an important task before us was to revitalise the planning process and to give a new thrust to the programmes of development. I am happy to say that, in the last four years, we have been able to achieve an unprecedented increase in the tempo of public investment.

36. For 1984-85, the approved Plan outlay of the Centre, States and Union territories will be Rs. 30,132 crores as compared to Rs. 25,480 crores in 1983-84. The Central Plan outlay for 1984-85 is Rs. 17,351 crores, which represents a step up of 25 per cent over the approved Plan outlay of Rs. 13,870 crores in 1983-84.

37. The Plan outlay for the States and Union territories is placed at Rs. 12,781 crores as compared with the final approved outlay of Rs. 11,678 crores in 1983-84. Central assistance for the Plans of States and Union territories will be Rs. 5,050 crores as against Rs. 4,462 crores in 1983-84 Budget Estimates, representing an increase of 13.2 per cent over the allocation made for the current year.

38. Within this aggregate, Plans of individual States show a varied picture. Some States have managed their finances well; they have been able to raise additional resources and effectively utilise these to implement adequately sized plans, providing development and growth to their people. Unfortunately, some States, for reasons of their own, have used their resources for various other purposes; they have not invested their resources, including additional resources mobilised, for development and have also resorted to large overdrafts on the RBI.

39. With a view to assisting even such States, various facilities and opportunities were provided from time to time. At the beginning of the Sixth Plan itself, recovery of outstanding advance assistance amounting to Rs. 1,412 crores was postponed. This was done to enable States to start with a clean slate. However, State overdrafts again grew, and in June 1982, I decided to clear States' closing deficits of the previous year with a medium term loan of Rs. 1,743 crores. RBI also doubled the ways and means limits available to the States. Again last year, while presenting the budget, I announced an increased level of Central assistance. All these measures were taken primarily to assist States to readjust their financial affairs and to be able to implement State Plans of adequate size.

40. Unfortunately, despite these measures, some States continued to rely heavily on overdrafts even after March 1982. Their proposed deficits at the end of March 1984

would have harshly affected their Plan sizes if these deficits were adjusted against next year's Plan, as per normal practice. In considering the ways of overcoming this problem, I have found myself in a predicament. On the one hand, no Finance Minister of the country can remain unconcerned about the size of a State's Plan. On the other hand, if assistance is extended to defaulting States, the well-managed States can legitimately complain that they have not got their just rewards from the Centre for their better performance.

41. In the past few weeks, discussions were again held with the Chief Ministers of States whose overdrafts with the RBI were high. Several State Governments have agreed to take the necessary measures to improve their financial position and to reduce their reliance on overdraft. On my part, I have agreed to take further steps to provide additional assistance to States in order to protect their Plans as far as possible. In doing so, I have been particularly conscious of the need to keep up the momentum of anti-poverty programmes. Central assistance is also being further increased. With this, the aggregate assistance during the Plan period will amount to Rs. 17,790 crores as against Rs. 15,350 crores envisaged in the Plan document. Further, as I mentioned earlier, I have made an additional provision of Rs. 500 crores in the Revised Estimates for 1983-84. This special assistance would enable these States to clear part of their overdrafts with the RBI. States have also been informed that closing deficits, upto the permissible ways and means limits from the RBI will not be adjusted from next year's Plan resources.

42. For those States who have managed their finances well, I am working out a suitable scheme to provide some additional assistance to them in 1984-85. This is only just and appropriate.

43. Mr. Speaker, Sir, I am sure that the House will agree with me that, despite severe resource constraints of its own, the Central Government has done the maximum that it can to solve the States' problems. The rest, however, is upto them.

44. Altogether, in the Sixth Plan period, the public sector Plan at current prices will be over Rs. 110,000 crores. This compares with Plan expenditure of Rs. 46,700 crores in the preceding five years, which, of course, include three years of "non-Plan" launched by the previous Government. In real terms too, the Sixth Plan will constitute a massive increase over the outlays provided for in any previous Plan. This, Mr. Speaker, is the measure of achievement of this Government in accelerating the pace of development in the current Plan period.

45. In the last four years, the present Government introduced a number of schemes for the benefit of the weaker sections of the society, particularly in the rural areas. These include the Integrated Rural Development Programme, the National Rural Employment Programme and two new programmes announced by the Prime Minister on 15th August, 1983, namely, the Rural Landless Employment Guarantee Programme and the scheme for providing self-employment opportunities to the educated unemployed. Each of these programmes is designed to create opportunities for employment and income generation for particular target groups, while also creating productive assets.

46. In formulating the next year's Plan we have provided the maximum support to these and other programmes that benefit the rural poor directly. The total allocation for various programmes of the Ministry of Rural Development would be Rs. 932 crores, which is nearly double the amount of Rs. 480 crores provided in 1983-84. For the IRDP an allocation of Rs. 216 crores is being provided, which is to be matched by the States. The number of beneficiaries under the programme in 1984-85 is estimated at over 3 million. For the NREP, the outlay for 1984-85 is Rs. 230 crores which will again be matched by the States.

47. The allocation for Rural Landless Employment Guarantee Programme, which seeks to provide employment for 100 days in a year to at least one member of every rural landless family, is being stepped up to Rs. 400 crores in 1984-85 as against a provision of Rs. 100 crores in 1983-84. This, together with the NREP, will provide 550 million man-days of work in rural areas in 1984-85. An allocation of Rs. 25

crores is being made for the programme for providing self-employment opportunities to the educated unemployed. As the House is aware, the budgetary provision under this programme will be used as capital subsidy against loans to be given by banks. I may add that for these two new programmes, depending on the progress of expenditure, more funds will be provided during the course of the year as necessary.

48. In the Plan for 1984-85, Rs. 243 crores have been earmarked for the accelerated rural water supply programme. The States on their part are expected to provide Rs. 364 crores for this purpose under the minimum needs programme. Over 50,000 problem villages are expected to be provided with drinking water facilities during 1984-85.

49. The programme for integrated child development services is an important part of our efforts to help women and children in the backward areas, urban slums and tribal areas of our country. This programme is already in operation in 820 blocks. By the end of 1984, the scheme will become fully operational in all 1000 identified blocks. A provision of Rs. 36 crores has been made for this scheme. A total allocation of Rs. 78 crores is being provided for various schemes of the Department of Social Welfare in 1984-85.

50. The provision in the Central Plan for the various programmes benefitting the scheduled castes and scheduled tribes and other backward classes has been increased to Rs. 209 crores in 1984-85 compared to Rs. 176 crores only in 1983-84. Plan outlay for the programmes in education and culture has been substantially stepped up to Rs. 204 crores in 1984-85 as against Rs. 155 crores in 1983-84. Likewise, the Plan outlay for health and family welfare programmes has also been stepped up by nearly 32 per cent from Rs. 460 crores in 1983-84 to Rs. 605 crores in 1984-85. The family welfare programmes will cover an additional 20 million persons.

51. These and other socio-economic priorities of the Government are reflected in the 20-Point Programme which is being vigorously implemented. The total amount allocated to the Programme in the Central Plan is Rs. 4038 crores, which is an increase of about 47 per cent over the current year's provision. Inclusive of the outlays to be provided by the States and Union territories, the total provision for the 20-Point Programme will be Rs. 11,858 crores, representing nearly 40 per cent of the total annual Plan outlay of the Centre States and Union territories.

52. An important source of strength for the economy has been the tremendous strides made in the agricultural sector. The next year's Plan will continue the high priority given by the present Government to the development of this sector. Thus, the total outlay for the various programmes of the Ministry of Agriculture will be Rs. 758 crores compared to Rs. 556 crores in the current financial year. The outlay includes Rs. 38 crores for the National Oilseeds Development Project which together with the on-going programmes, visualises an additional production of 9.4 lakh tonnes during 1984-85 itself.

53. To further strengthen the country's infra-structure, higher allocations are being provided for power, coal, railways and ports. The total provision for various power projects adds to Rs. 1764 crores, which represents a 44 per cent increase over 1983-84. The allocation for projects of the Department of Coal is Rs. 1310 crores as against Rs. 1076 crores in 1983-84, and the target for coal production is 152 million tonnes in 1984-85. The provision for the Railways in 1984-85 is Rs. 1650 crores, which is 23 per cent higher than the current year. It is expected that the revenue earning traffic to be carried by the Railways will increase to 245 million tonnes in 1984-85. An allocation of Rs. 201 crores is being made for the development of ports, including Rs. 27 crores for the deepening of the Madras harbour.

54. An outlay of Rs. 3127 crores is being provided for petroleum. This includes a sum of Rs. 2685 crores for the programmes of exploration and production, and Rs. 443 crores for the various schemes of refining and marketing. The target for production of crude oil in 1984-85 is about

30 million tonnes. A provision of Rs. 200 crores is also being made for a gas pipeline project for supply of Bassein gas to new fertilizer projects to be set up at Bijapur, Jagdishpur, Aonla, Babrala, Shahjahanpur and Sawai Madhopur.

55. Higher allocations have been provided for steel, non-ferrous metals, paper, cement and several other sectors, which are important for country's industrial development. I would also like to draw the attention of the House to the programmes for the development of science and technology, conservation of natural resources, and improvement of the environment in the Plan for 1984-85. The successful positioning of INSAT-1B in a geostationary orbit in August last testifies to the excellent work done by our scientists, engineers and technicians. It is also a matter of pride to us that India has joined a select group of countries which have permanent scientific stations in the Antarctica. India has also achieved the distinction of being the only developing country to be given the status of 'pioneer investor' by the Convention on the Law of the Sea, giving us the right to exploit the mineral resources of the deep sea beds.

56. Finally, I should mention that the incentive schemes for better performance in selected areas, initiated in 1983-84, will continue in 1984-85 also. As the House is aware, these schemes are designed to improve the functioning of the electricity boards, and provide further impetus to the programmes for small and marginal farmers, rural water supply schemes, environmental improvement in urban slums, construction of field channels in command area development projects, and adult education for women and elementary education for girls. A lumpsum provision of Rs. 200 crores is being made for this purpose. I trust the Hon'ble Members take me to be a magician, who can do so much with so little. I hasten to clarify that the incentive scheme is designed to provide additional resources linked to performance for specified schemes. There are, of course, also separate substantial allocations for each of these schemes.

57. I have only briefly touched upon the main priorities and objectives of the Annual Plan for 1984-85. Further details are available in the budget documents.

58. In order to provide the maximum possible outlay for the Plan, I have taken special care to ensure that non-Plan expenditure is kept at the minimum. However, certain increases are necessary and unavoidable. I should also add that the estimates of receipts from and payments to State Governments take into account the recommendations contained in the interim report of the Fifth Finance Commission. I have already kept the House informed of this. The final report of the Commission is now expected by the end of April, 1984.

59. I have provided Rs. 6800 crores for Defence expenditure next year against the Revised Estimates of Rs. 6350 crores. I am sure the House will agree that the requirements for Defence have to be met fully to protect the security of the country. Interest payments next year are estimated at Rs. 5600 crores against Rs. 4850 crores in the current year. The borrowings are largely for financing our developmental efforts, and the increase is due to the success of our policies for mobilising savings. A provision of Rs. 850 crores has been made for food subsidy. The requirement for subsidy on indigenous and imported fertilizers is placed at Rs. 1080 crores. Export promotion and market development have been allocated Rs. 530 crores.

60. A lumpsum provision of Rs. 300 crores has been made in 1984-85 for payment of additional instalment of dearness allowance, pensionary relief, etc. to Central Government employees. Including these and, inter alia, provisions which are in the nature of adjustments, total non-Plan expenditure in 1984-85 is estimated at Rs. 26,066 crores against Rs. 24,773 crores in Revised Estimates for 1983-84.

61. Turning to receipts in 1984-85 the gross tax revenues at existing levels of taxation are estimated at Rs. 22,993 crores compared with Rs. 20,946 crores in the Revised Estimates. The States' share of taxes in 1984-85 is estimated at Rs. 5739 crores as against Rs. 5246 crores in the current

year, which is an increase of nearly Rs. 500 crores. The net tax revenues of the Centre will thus be Rs. 17,254 crores compared with Rs. 15,700 crores in the current year. The dividend from Railways and Posts and Telegraphs will be higher by Rs. 106 crores than the Revised Estimates for 1983-84. Interest receipts and repayment of loans by public sector undertakings and State Governments will also be higher.

62. Receipts from market loans are placed at Rs. 4100 crores against Rs. 4000 crores in the current year. Small savings collections are estimated at Rs. 2400 crores against Rs. 2200 crores in the current year. External assistance net of repayments is estimated at Rs. 2089 crores compared with Rs. 1902 crores. Next year's Budget also includes a receipt of Rs. 200 crores from the National Deposit Scheme to which I have referred in the earlier part of my speech. Taking into account these and other variations in receipts, the total receipts in 1984-85 are estimated at Rs. 40,501 crores. These receipts include the effect of the changes in fare and freight rates of the Railways. The total expenditure is placed at Rs. 42,536 crores. The overall budgetary gap at existing rates of taxation will thus be Rs. 2035 crores.

63. I have taxed the patience of the House enough. Let me now turn to other tax proposals.

(PART B)

64. In framing these proposals, I have tried to take into account the realities of the economic situation to which I referred at the beginning of my speech. While doing so, I hope I have not been entirely unkind of a certain forthcoming event which is of importance to all of us in this Parliament.

65. Mr. Sptaker, Sir, my first proposal relates to the non-corporate income-tax sector. I propose to revise substantially the entire rate structure relating to personal taxation. The present rate of tax in the first slab of taxable income ranging from Rs. 15,001 to Rs. 20,000 is 25 per cent. The House will recall that this rate was brought down last year from the then prevailing level of 30 per cent. I now propose to reduce this rate further to 20 per cent. Relief has been allowed at all income levels above Rs. 20,000 also. The maximum marginal rate of tax on incomes over Rs. 1 lakh is being reduced from 60 per cent to 55 per cent. The new rates in some illustrative slabs will be as follows: in the income slab of Rs. 25,001 to Rs. 30,000, the new rate will be Rs. 30 per cent as against 35 per cent at present; in the income slab of Rs. 50,001 to Rs. 60,000, the new rate will be 45 per cent as against 50 per cent at present; and in the income slab of Rs. 70,001 to Rs. 80,000 the new rate will be 50 per cent as against 55 per cent at present.

66. The above proposal will provide relief at all levels of incomes. Taken with the increase in the standard deduction introduced last year, I expect this measure will provide substantial relief in particular to the fixed income groups. The revised tax schedule will provide a relief in tax of Rs. 281 to a taxpayer with an income of Rs. 20,000, which is 20 per cent of the tax payable by him earlier. For an income level of Rs. 30,000, the relief will be Rs. 844 or 16.7 per cent of the tax payable under the old structure, and at income level of Rs. 50,000, this relief will be 10 per cent of the tax payable.

67. The loss of revenue in the proposed rate schedule, assuming no change in the number of taxpayers and the assessed incomes in different income slabs, is calculated at Rs. 180 crores. However, lowering of the tax rates should normally be expected to lead to an increase in the coverage of taxpayers in different tax slabs and also better tax compliance. Taking these factors into account, I have assumed a net revenue loss of Rs. 59 crores only. This loss is entirely attributable to tax relief provided to the fixed income groups. As far as business and professional incomes are concerned, I have assumed that the reduction in the rates will encourage better compliance and reporting and that this will partly cover the revenue loss.

68. This proposal, Mr. Speaker, Sir, in a way continues the tax rationalisation programme that was started by my Party in 1974; carried forward in 1976 and further reinforced after we came back to power in 1980. The present

tax structure has also been brought down to a level which I regard as realistic and entirely appropriate. I hope this measure will have a salutary effect on our tax culture and will induce the maximum number of taxpayers to come forward and voluntarily declare their true incomes.

69. At the same time, it is necessary to simplify tax administration and make it more responsive to the needs of the taxpayers. One essential feature would be the effort to complete assessments within the shortest possible time. As the Hon'ble Members are aware, the scope of the summary assessment scheme covers incomes upto Rs. 1 lakh. Only a percentage of cases with incomes in this range is being scrutinised, the selection of such cases being on random sampling basis. The target for 1983-84 is to complete 85 per cent of the summary assessments workload. I have instructed the Income Tax Department to further speed up the assessments.

70. For some years, the Income-tax Act has contained provisions empowering the Central Government to acquire immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000. This power is exercisable in situations where the declared consideration for transfer of the property is less than the fair market value of the property. To eliminate unproductive work in handling a large number of relatively small value cases and also taking into account the rise in market prices I have modified the provision to say that this power will be exercised only in cases where the fair market value exceeds Rs. 50,000. As a further simplification it is being provided that the prescribed statement will have to be filed before the registering officer only in cases where the value of consideration for the transfer exceeds Rs. 25,000 as against Rs. 10,000 at present.

71. With the reduction in rates and expeditious disposal of assessments, I believe there can now be no excuse for any leniency to be shown to those who abuse our laws. Such cases will necessarily have to be dealt with severely. In order to discourage tax avoidance and tax evasion, I am also introducing some further measures. In all cases where the annual turnover exceeds Rs. 20 lakhs or where the gross receipts in a profession exceed Rs. 10 lakhs, I am providing for a compulsory audit of accounts. This is intended to ensure that the books of account and other records are properly maintained and faithfully reflect the true income of the taxpayer. I am also proposing that loans or deposits of Rs. 10,000 or more shall be taken or accepted only by crossed cheque or bank draft.

72. I find that the existing provisions of the Income-tax Act provide that no suit to enforce any right relating to any property held benami can be instituted in any court by a person claiming to be the legal owner unless he has declared the income from such property in any return of income or the value of such property in any return of net wealth or furnished a notice in this behalf in the prescribed form to the income-tax Officer. Such return or notice can at present be given at any time before the suit is filed. With a view to curbing the practice of benami holding of property I am proposing that it will henceforth be obligatory in all cases to give notice to the Commissioner of Income-tax in the prescribed form within one year of the acquisition of the property. This amendment will enable the Department to initiate appropriate action in respect of such benami acquisition of property well before the limitation for such action expires.

73. Having dealt with the non-corporate sector, I now turn my attention to the corporate sector. The tax rates for this sector are not being changed. I am however providing one facility. Last year, while raising the surcharge payable by companies from 2.5 per cent to 5 per cent, I had given companies the option to make deposits of the additional surcharge with the Industrial Development Bank of India. I am now further providing that companies can henceforth exercise this option in respect of the entire amount of the surcharge payable by them. These resources will flow back to the corporate sector, and will be available for modernisation. In the earlier part of my speech, I have already referred to the decision to reduce the interest rates on loans upto Rs. 4 crores being extended by IDBI under the soft loan scheme.

74. Representations had been received from various quarters that the ceiling on the deductible amount of managerial

remuneration as contained in the Income-tax Act is low and should be raised. I am glad to inform the House that having regard to the changes in the managerial remuneration introduced by the Department of Company Affairs, I am also raising the ceiling limits for managerial salaries from Rs. 5,000 to Rs. 7,500 per month. The ceiling in respect of perquisites will however remain unchanged.

75. Some relaxations are also being provided to those engaged in the business of growing and manufacturing tea. The existing provisions provide exemption from tax only in respect of subsidy received for replantation or replacement of tea business. I am extending this tax exemption to cover subsidy received for other approved schemes relating to rejuvenation and consolidation of areas. I hope this measure will further lend support to our scheme for increasing production of tea.

76. My next proposal, I believe, will be welcomed by a large number of people. Investors presently can receive dividends and interest on debentures without deduction of tax at source, if they furnish an exemption certificate from the Income-tax Officer or alternative file a declaration to the effect that their income for the year is below the exemption limit. To reduce paper work and avoid inconvenience to small investors, I propose to provide that widely-held companies may, henceforth, pay interest on debentures and dividend income upto Rs. 1,000 without deduction of tax at source provided that the payment is made by an account payee cheque or a bank draft.

77. Mr. Speaker, Sir, I notice that certain provisions of tax laws are being misused by a section of the taxpayers. I had occasion last year to deal at some length with taxation of charitable and religious trusts and institutions. I find that some of these trusts and institutions are trying to circumvent the investment pattern for trust funds laid down by the Finance Act, 1983. It is necessary to ensure that all such trusts and institutions strictly conform to the prescribed investment pattern and that such income or property is not used for providing benefit to the settlors, trustees, etc. I, therefore, propose to provide for taxation of the income of defaulting trusts and institutions at the maximum marginal rate of income-tax.

78. While on this subject, I would like to refer to a tendency noticed to create private trusts which carry on business. To curb such practice, I propose to provide that where such trusts have profits and gains of business, the entire income of the trust will be charged to tax at the maximum marginal rate, an exception being made only in the cases where the trust is created by will for dependant relatives.

79. Another undesirable practice noticed is the tendency of some corporate bodies to make large contributions to the so-called welfare funds. I further understand that utilisation of these funds is discretionary and subject to no discipline. I am, therefore, providing that deduction will be available only in respect of contributions to such funds as are established under statute or an approved provident fund, superannuation fund or gratuity fund. I am making this change with retrospective effect to avoid unnecessary litigation.

80. Last year, I liberalised the scheme related to export turnover. I propose to continue it and watch its operation for a longer period of time.

81. Last year, I had also referred to a large variety of exemptions and deductions that had been built into our tax system over time. While each deduction by itself may have its own merits, the aggregate effect was to complicate the tax administration and to provide loopholes for tax avoidance or tax evasion, as also for litigation. I had, therefore, initiated a process of review and, where necessary, doing away with concessions which had outlived their utility. I intend to carry this process further.

82. Our experience has shown that an expenditure related concession leads to a tendency to inflate expenditure and hence it should have no place in our tax system. Therefore, I propose to withdraw all weighted deductions as are available under the different provisions. The expenditure actually incurred will of course, continue to qualify for deduction. Only the benefit of weightage will no longer be available.

83. I am also withdrawing the exemptions available under sections 33B, 35C, 80CC, 80D and 80E of the Income-tax Act. These deductions, notwithstanding their apparent laudable objectives have either been open to misuse or have benefitted only a few. The revenue involved is marginal. I am also reducing the quantum of exemption available under Sections 80M, 80N and 80-O.

84. Now, I intend to announce a few concessions in respect of the Wealth-tax Act. Hon'ble Members, I am sure, will be happy to hear that the monetary ceiling of exemption in respect of one house owned by a taxpayer is, being increased from the present level of Rs. 1 lakh to Rs. 2 lakhs. This is being done to take into account the increase in market value. I am also proposing to raise the exemption limit in respect of specified financial assets from the present level of Rs. 1,65,000 to Rs. 2,65,000. Together with separate exemption of Rs. 35,000 available in respect of units of the Unit Trust of India and proposed to be extended to deposits under the National Deposit Scheme, the aggregate exemption in respect of the value of specified financial assets will rise to Rs. 3 lakhs as against the present ceiling of Rs. 2 lakhs. Hon'ble Members would recall that in the earlier part of my speech, I had referred to the success in mobilising savings in the form of financial assets; I hope that this change will give further impetus to it.

85. The other changes proposed by me in respect of direct taxes are of relatively minor nature and I would not like to take the valuable time of this House by elaborating them.

86. After adjustment of the gain to revenue on account of withdrawal or modification of certain concession, my proposal in regard to income-tax will lead to a net loss of Rs. 75 crores, of which the loss to the Centre would be Rs. 36.22 crores and the loss of the States would be Rs. 38.68 crores.

87. Mr. Speaker, Sir, I shall now deal with my proposals in the area of indirect taxes. Here my main objective has been to provide further impetus to the growth of Indian industry through tariff adjustments and substantial relief in excise duties in carefully selected areas. I have also kept in view the need to reduce prices of certain items for consumers and contain the rate of inflation in the economy. I am sure the Hon'ble Members will not grudge, if in doing so, I have also taken a little care of Government revenues.

88. My principal proposal relating to customs duties is with regard to auxiliary duty of customs. The levy imposed on an annual basis since the 1973 Budget is proposed to be continued upto the 31st of March, 1985. I also propose to raise, with certain exceptions, the present effective rates by 5 percentage points. I am excluding from the proposed increase essential items like fertilizers, bulk petroleum products such as kerosene and high speed diesel oil, and also newsprint. Fuller details of these proposals are available in the Budget papers. This proposal is expected to yield an additional revenue of Rs. 241.73 crores in a full year.

89. The present customs duty on crude petroleum of Rs. 9.50 per metric tonne (which is being collected by way of auxiliary duty) was fixed in 1973. Without affecting the domestic prices of petroleum products, I propose to raise the duty on crude to Rs. 100 per metric tonne. The revenue gain from this measure will be Rs. 132.76 crores. This duty increase is to be absorbed by the oil companies without their having to raise consumer prices on this account.

90. The current rates of import duties on iron and steel items were fixed a few years back and they are now out of line with the requirements of indigenous industry. I propose to raise the basic customs duty on different items of iron and steel (other than stainless steel) by 5 percentage points or 10 percentage points, depending upon the existing rates of duties. I also propose to levy a total customs duty of 20 percent ad valorem on stainless steel melting scrap, which is presently exempt from customs duty. These measures are expected to yield an additional revenue of Rs. 84.20 crores.

91. I also propose to increase the import on duty zip fasteners and parts thereof, magnetic tape and petroleum specialities, namely petroleum jelly, sodium petroleum sulfonate and liquid paraffin. Details of the proposals are available

in the Budget papers. The revenue gain in these proposals would be of the order of Rs. 5.32 crores.

92. In order to promote exports in the important sector of gems and jewellery, customs duties leviable on a number of gems and jewellery processing and manufacturing machines are proposed to be reduced from the respective existing rates to 40 per cent ad valorem. The gem processing machines would enable significant reduction in processing losses and also improve overall quality and productivity. Similarly, I also propose to reduce customs duties on specified machines used in packaging of food articles as well as by meat and food processing industries from the respective existing rates to 40 per cent ad valorem. This measure is expected to encourage export of food items in value-added form and also in consumer packs instead of in bulk. The revenue sacrifice involved in the above proposals is of the order of Rs. 5.24 crores.

93. With the advancement in machine tool technology, CNC machines are progressively replacing conventional machine tools due to their higher productivity and accuracy. To enable the indigenous machine tool manufacturers to offer CNC machine tools on competitive terms, I propose to reduce the customs duty on CNC systems to 35 per cent. The revenue sacrifice is of the order of Rs. 0.82 crore.

94. To enable the paper industry to obtain its raw materials at reasonable prices and to relieve the pressure on our forest resources, I propose to totally exempt from customs duties wood chips for making pulp for the manufacture of paper or paper board. On similar considerations, I propose to reduce the duty on wood pulp imported for manufacture of paper from the existing levels to 30 per cent. These measures involve revenue sacrifice of the order of Rs. 1.10 crores.

95. Certain changes in the provisions of the Customs Act, 1962, relating to warehousing, etc. and in the Customs Tariff Act, 1975 are also proposed. The details of these proposals have been given in the Budget papers.

96. Sir, coming now to new proposals in respect of excise duties, my main objectives are to minimise the effects of inflation, lessen scope for tax avoidance and evasion, give a boost to selected industries suffering from demand recession, and ensure better utilisation of the capacity and investment already created.

97. I propose to continue upto 31st March, 1985 the levy of special excise duties at the existing rates and with the existing exemptions.

98. My first proposal for relief is in respect of khandsari sugar. I propose to fully exempt khandsari sugar from the levy of excise duty. I am taking this measure in view of the labour-intensive character of this industry, and to provide further opportunity for growth of employment in this industry. The abolition of excise duty will also help this industry to pay better price to cane growers, and will give relief to a large number of khandsari units located in far-flung rural areas. The revenue sacrifice involved in this proposal is Rs. 16.42 crores. Khandsari, I am told, is also better for health. If as a result of this measure, the health of the nation improves, I hope the credit will flow to me and not to my distinguished colleague, the Health Minister!

99. Hon'ble Members would recall that excise duty was levied on electricity as a revenue measure in the 1978 Budget. The net proceeds from the duty collected on electricity are wholly distributed to the States. It is proposed to abolish the excise duty on electricity leaving it to the State Governments to tap this source, to whatever extent and in whatever manner they like. This will give to the States one more area for resource mobilisation. To give the States some time to take appropriate action, this abolition will be effective from 1st October, 1984.

100. I also propose to provide substantial relief to the textile industry with a view to making cloth cheaper. Hon'ble Members may recall that in the 1982 and 1983 Budgets, excise duty was reduced to encourage the production of blends with the desirable proportions of polyester. Such fabrics are becoming increasingly popular with the people.

As a further measure of relief in this area and with the overall objective of making such fabrics available at lower prices, I propose to reduce the total excise duty on polyester-cotton blended yarn containing more than 40 per cent but less than 70 per cent polyester to Rs. 5 per kg. The existing rates of duty on such yarn vary generally from Rs. 7.5 per kg. to Rs. 22.5 per kg. depending on the extent of polyester-cotton mix. Under my proposal all blends over 40 per cent but below 70 per cent of polyester will pay the same reduced rate of duty. For similar blends of polyester and viscose, the excise duty will get reduced to Rs. 10 per kg. from the present rates which generally vary from Rs. 11.25 per kg. to Rs. 22.50 per kg. The revenue sacrifice on these accounts is estimated at Rs. 33.25 crores in a full year.

101. Blended fabrics have also received my attention. The excise duty on polyester-cotton blended fabrics containing more than 40 per cent but less than 70 per cent polyester will be reduced to 2 per cent ad valorem. The incidence of duty on such fabrics at present varies from 7.5 per cent to 17.8 per cent ad valorem. This concession would cost the exchequer Rs. 26.50 crores in a full year. I also propose that this duty at 2 per cent ad valorem be collected as additional excise duty in lieu of sales tax. As Hon'ble Members are no doubt aware, proceeds of additional excise duties on textiles go to the States.

102. These changes in the duty structure on polyester-cotton blended yarn and polyester-cotton blended fabrics will for a 67 : 33 blend, reduce the duty incidence by about Rs. 3.30 per square metre on a fabric carrying a wholesale price of about Rs. 25 per square metre, and a retail price of Rs. 35 to 40 per square metre. This duty reduction will enable the industry to sell such fabrics at reduced prices.

103. I also propose to provide relief on cotton fabrics which still constitute a major share of the total production of cloth in the country. I propose to reduce excise duty on cotton fabrics of less than 51 counts and of assessable value not exceeding Rs. 5 per square metre. Such fabrics at present pay duty of excise at rates varying from 2.38 per cent to 3.56 per cent ad valorem in the case of composite mills. Concessional rates of duty are allowed for independent processors processing powerloom and handloom fabrics. I propose to fully exempt handloom and powerloom fabrics of the above varieties processed by independent processors. The rate of duty for composite mill fabrics is also being reduced to 1 per cent ad valorem retaining more or less the present differential between the independent processors and the composite mills. This duty would be in the nature of additional excise duty in lieu of sales tax and will entirely go to the States. Such fabrics are mostly consumed by the weaker sections of society. The benefits of the reduction should become available to them in the form of lower prices. This proposal on cotton fabrics would entail a revenue sacrifice of Rs. 28.40 crores.

104. I hope, my proposals would also help the textile industry. The industry should benefit through increased demand that lower prices would generate.

105. Cotton yarn and cellulosic spun yarn in the form of cross reel hanks are finding increasing use in the handloom sector. In the Handloom Year, I propose to reduce the duty incidence on such yarn supplied to registered Handloom Cooperative Societies or to organisations set up or approved for the development of handlooms by about 50 per cent. This would involve a loss of Rs. 3 crores to the exchequer in a full year.

106. In order to recoup some of the revenue loss flowing from the above package of measures in respect of the textile industry, I propose to increase the incidence of additional excise duty in lieu of sales tax from 7.5 per cent to 10 per cent on man-made fabrics of assessable value exceeding Rs. 25 per square metre. This increase will not apply to those blended fabrics in respect of which duty is being reduced. The impact will be on costlier fabrics which are consumed mainly by the more affluent sections of society. They should not mind this. On this account, the exchequer will gain by Rs. 27 Crores in a full year and this, too, would accrue entirely to the States.

107. I also propose to reduce the duty on shoddy blankets and other similar blankets made from shoddy yarn processed by composite mills by about 7 per cent. Such shoddy blankets if processed by independent processors will be wholly exempt. The revenue loss on this account would be Rs. 1 crore in a full year.

108. Another industry needing urgent attention is the paper industry. This industry has been passing through a difficult phase troubled by rising cost of raw materials and other inputs. My proposals aim at encouraging the production of paper and paper board and preserving scarce natural forest resources. I have already referred to the proposed exemption from customs duty on import of wood chips and wood pulp for paper making. As a further measure of relief, I propose to reduce the basic excise duty on printing and writing paper and also kraft paper produced by large paper mills by Rs. 425 per metric tonne, and corresponding concessions are being given on the duty leviable on such paper when unconventional raw materials are used in their manufacture. Simultaneously, the range of permissible unconventional raw material is being expanded.

109. No concession for use of unconventional raw material is presently available in the case of paper boards. I propose to reduce the basic excise duty payable on paper boards manufactured from at least 50 per cent unconventional raw materials from the present general level of 10 per cent ad valorem + Rs. 1430 per metric tonne to Rs. 560, Rs. 900 or Rs. 1120 per metric tonne depending on whether the clearances of paper and paper board from such paper mills in the preceding financial year did not exceed 3,000 tonnes, 7,500 tonnes or 16,500 tonnes respectively. For larger paper mills using unconventional raw materials, the rate of basic excise duty on paper boards is being reduced to 7 per cent ad valorem + Rs. 925 per metric tonne.

110. My proposals relating to the paper industry would entail a loss of Rs. 33 crores in excise duties in a full year. Along with the customs duty exemptions on import of wood chips and wood pulp, this package is expected to provide substantial fiscal support to the development of indigenous paper industry and improve the availability of paper at reasonable prices.

111. Hon'ble Members may recall that certain time bound concessions were given in October, 1983, in respect of certain specified commodities. Having regard to the industry's response to that measure which was intended to stimulate production by generating incremental demand, I propose to continue the concession for one year with certain modifications.

112. In the case of commercial vehicles and three-axled vehicles, the concession will be continued but the extent of duty concession granted in October, 1983 is being reduced by 2-1/2 percentage points. I propose to remove some models of light commercial vehicles from the purview of the exemption in order to establish parity among all models of such vehicles in the matter of the rate of excise duty. These proposals would entail a revenue loss of Rs. 45 crores in a full year.

113. I propose to continue the concessions in the case of refrigerators, deep freezers and parts of refrigerating appliances etc., storage batteries and domestic electrical appliances. The total revenue sacrifice on these items would be to the tune of Rs. 19 crores.

114. In the case of tyres for buses and trucks and tyres for use off-the-road, I do not propose to continue the concession granted in October, 1983 as there is no further case for this concession in view of the price increases announced by this industry. However, as a measure of rationalisation and in order to reduce scope for tax evasion, I propose to switch over by and large to a system of specific rates of duties from the ad valorem rates.

115. Production of china and porcelain tableware over the last few years has been showing signs of stagnation and the capacity utilisation has been declining. With a view to providing relief to the industry I propose to reduce the basic excise duty from 30 per cent to 15 per cent on these items. This would entail a revenue loss of Rs. 15 crores.

116. With summer not very far away, I would like to help the Hon'ble Members in keeping their tempers cool. I propose to reduce basic excise duty on table fans from 10 per cent to 5 per cent and on ceiling fans of a diameter not exceeding 107 cms from 15 per cent to 7.5 per cent. I also propose to reduce the basic excise duty on evaporative type of coolers, including desert coolers, from 40 per cent to 30 per cent ad valorem. These proposals would involve a revenue sacrifice of Rs. 5.10 crores.

117. As a rationalisation measure, I propose to reduce the basic duty on winding wires from 10 per cent to 5 per cent and increase the basic duty on copper wire rods by Rs. 1300 per metric tonne. On an overall basis, these changes will neither result in a loss nor gain in revenue.

118. As Hon'ble Members will remember, many reputed artistes had published an appeal inviting our attention to piracy. As I "just can't write these names off" I propose to exempt sound-recorded cassettes wholly from excise duty. In view of the upward revision of customs duty on magnetic tapes, the revenue loss on this account is expected, by and large, to be made-up.

119. As a general measure of relief I propose to fully exempt laundry soap manufactured by KVIC units and to reduce basic excise duty from 10 per cent to 5 per cent on certain mass consumption items such as imitation jewellery, stainless steel utensils, glass chimneys for lanterns, high efficient wood burning stoves, umbrellas and saccharine. The revenue sacrifice involved in these concessions is Rs. 1.13 crores.

120. Hon'ble Members may recall that an excise duty relief scheme to encourage higher production is in operation for the past two years. I propose to continue the scheme for one more year.

121. Hon'ble Members would also recall that in the last Budget, I had rationalised the tariff relating to iron and steel items. This year, I have undertaken a similar exercise in respect of non-ferrous metals. The tariff entries are being revised on a more scientific basis. These changes as in last year would be brought into effect from a subsequent date. Till then, the present effective rates of duty would continue.

122. I propose to increase the additional excise duty in respect of cigarettes. The present ratio between basic excise duty and additional excise duty is being altered to 1.75 : 1. This measure will result in the transfer of Rs. 42.89 crores from the basic excise duty account to the additional excise duty account in the next financial year, and thus increase the accrual to the States. There will be a corresponding reduction in the amount allocated to basic excise duty. The total incidence of excise duties on cigarettes will remain unaltered.

123. There are some other minor proposals which do not have much revenue significance. These include readjustment of duties in some cases and deletion of some tariff items which have remained fully exempted for a long time.

124. In the light of the experience gained in the working of the Income Tax Appellate Tribunal and the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal, some amendments are proposed to be carried out in the laws relating to them. These are mainly of an administrative nature. I do not propose to take the time of the House over these proposals.

125. Mr. Speaker, Sir, with the phenomenal increase in central excise revenue from about Rs. 100 crores in 1953-54 to about Rs. 10100 crores in 1983-84, the Central Excise Tariff has also substantially grown. I think, it is time to make a comprehensive review of the tariff as it has developed over the last three decades with a view to rationalising it. This would require a detailed study which can best be done only by a technical study group. I propose, therefore, to appoint such a Group.

126. The proposals that I have presented will yield additional revenue of Rs. 465.41 crores in customs duties and Rs. 33.10 crores in excise duties. There would be a transfer of Rs. 43.64 crores from the basic duty account to the additional duty (in lieu of sales tax) account. The concessions and

reliefs aggregate Rs. 7.26 crores on the customs side and Rs. 222.43 crores on the excise side. The net yield from customs duties is Rs. 458.15 crores. The net loss from excise duties comes to Rs. 189.33 crores out of which Centre's share would be Rs. 148.95 crores and States' share would be Rs. 40.38 crores. This takes into account the States' share from additional excise duties in lieu of sales tax to the extent of Rs. 52.31 crores. The accrual to the central exchequer for the additional tax effort in a full year would be Rs. 309.20 crores.

127. Copies of notifications giving effect to the changes in customs and excise duties effective from the 1st March, 1984 will be laid on the Table of the House in due course.

128. I had earlier stated that the budgetary deficit at the existing rates of taxation would be Rs. 2035 crores. The tax measures proposed now, taken together with reliefs and concessions, are estimated to yield net additional revenue of Rs. 272.88 crores to the Centre. This leaves an uncovered deficit of Rs. 1762 crores. It has been my endeavour to keep the budgetary deficit to a relatively low figure and I am sure

the Hon'ble Members would agree that this order of deficit is appropriate to our circumstances. I hope that the low deficit, combined with my proposals for boosting production and lowering prices, will have a salutary effect on the inflationary psychology in the economy.

If I may, at this point, quote from Kautilya's Arthashastra :—

एवं कुर्यात्समूह्यं वृद्धिं चायस्य दर्शयेत् ।
हासं व्ययस्य च प्रपन्नः साधयन् च विपर्ययम्

129. Four years ago, my distinguished predecessor, while presenting the first Budget of the present Government, had expressed our firm resolve to repair the damage and restore the country's economy to the path of stability, growth and social justice. Mr. Speaker, we have kept that promise.

130. I commend this Budget to the House.

A. RANGACHARI, Jt. Secy.

